लोक शक्ति मंच का अब तक का सफर

2008 सितम्बर से 2015 अगस्त

परिचय

लोक शक्ति मंच 2008 से समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ मुख्य रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है मंच की संगठनात्मक संरचना समुदाय के लोगो से ही बनती है जिसमे समुदाय के सभी लोग (महिला, परुष, युवा और बच्चे) शामिल है जिनके साथ मंच जन जागरूकता (पालिसी एडवकेसी) का कार्यक्रम चला कर समुदाय का सशक्तिकरण का काम करता है अर्थात यह लोगों का संगठन है जिसकी गतिविधियाँ लोगों द्वारा ही चलाई जाती है | मंच के तहत समुदाय के सभी लोग अपने संवैधानिक हकों के संघर्ष के लिए एकजुट हो आगे बढ़ते है, जिसमे मंच की भूमिका लोगों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की रहती है |

कार्यक्षेत्रों का परिचय

1. दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अपना अपना शासन चला रही है इसके बावजूद दिल्ली की 60 फीसदी लोग गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रहे है आकड़ों की माने तो 52 फीसदी लोग मलीन बस्तियों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे है और पुनर्वास बस्तियों का हाल इससे भी ज्यादा है लोगो को पुनर्वास के नाम पर उजाड़ कर शहर से बाहर (हाशिया) पटक दिया गया है हम दिल्ली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काम कर रहे है जिसमे मुख्य रूप से भलस्वा पुनर्वास कालोनी और जहांगीरपुरी की बस्तिया है जो की दिल्ली के सबसे बड़े लैंडफील के पास बसाई गयी है जहाँ जन सुविधा तो दूर की बात है वातावरण भी दूषित है |

2. उत्तर प्रदेश बलिया जिले के कर्णछपरा गाँव में खेती हर किसान और भूमिहीन मजदूर किसान जिनकी आर्थिक और समाजिक स्थिति बहुत दयनीय है भले ही आज सरकारी योजनाओं के तहत गाँव के लिए बहुत सी योजनाये (ग्राम विकास, मनरेगा आदि) चल रही है लोगों के पास जानकारी नहीं होने की वजह से सारी योजनाओं का लाभ गाँव के दबंग नेता प्रधान और अधिकारियों ने विकास के पैसे की लूट मचा रखी है कुछ युवा जो पढ़े लिखे है वह अच्छे अवसर की तलाश में शहरों की और पलायन कर रहे है |

उपरोक्त शहर और गाँव दोनों में बदलाव की बहुत जरूरत है इस स्थिति के लिए लोगो को जागरूक कर सशक्त करने की कोशिश में मंच कार्यरत है |

मुद्दे

लोक शक्ति मंच का अपना कोई मुद्दा नहीं है इसलिए मंच लोगों की जरूरतों और मांग पर काम करता है अब तक का सफर शहरी क्षेत्र में राशन, पानी, बिजली, साफ़ सफाई, शिक्षा आदि मुद्दों पर काम किया है |
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास के मुद्दों व मनरेगा पर हो रही धांधली को लेकर काम किया है |

कार्य पद्धति / गतिविधियाँ

लोगों के बीच जाना उनकी समस्याओं को जानना नुक्कड़ मीटिंग व पब्लिक मीटिंग करना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, चिठ्ठियाँ लिखना, विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें, सूचना का अधिकार का प्रयोग करना, प्रचार समाग्री का प्रयोग (पर्चा बाटना, पोस्टर लगाना, बैनर का प्रयोग, स्टीकर आदि) करना मुद्दों पर समझ बनाने के लिए विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन करना, नेटवर्क बढाना, सीखना सीखाना आदि |

उपरोक्त गतिविधियाँ को करते हुए मुख्यतः तीन तरह की बातें निकलती है |

1. विभागों के साथ बैठकें कर और सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सूचना निकलना |
2. सूचना को जन समुदाय में बाटना और जागरूक कर समुदाय को सशक्त करना |
3. लोगों और विभाग के बीच समंवय स्थापित करना जिससे शिकायतकर्ता और निवारणकर्ता आपस में समाधान कर सके |

सरकार बदले या अधिकारी, समुदाय की स्थिति जस की तस

हमारे देश में ग़रीबों के वोटों की राजनीति ज्यादा पलती है हर नेता देश के विकास की परिभाषा अपने तरीके से करता है विकास का मतलब बड़े फ्लाई ओवर, मौल, चौड़ी चमचमाती सड़कें, मेट्रो और अब बुलट ट्रेन आदि है यही परिभाषा है स्मार्ट सिटी व वर्ल्ड क्लास सिटी की | जबकि इन समुदाय में रहने वाले लोग इन सभी चीजो का प्रयोग ज्यादातर नहीं ही कर पाते |

लोगों की जरूरत है रोजगार, आवास और जनसुविधा कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती | अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है | जैसे -

1. दिल्ली में 20,000 लीटर पानी लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है लेकिन इन समुदायों में पानी के कनेक्शन भी नहीं है | DJB ने यह कह दिया हम भलस्वा को पानी ही नहीं दे सकते |
2. उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख का लोन दिया जा रहा है लेकिन समुदाय में ठीक से स्कूल की व्यवस्था ही नहीं |
3. पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल यहाँ है लेकिन यहाँ गंदे पानी की निकासी भी नहीं आदि |

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है की यह वर्ग विकास की मुख्य धारा से बाहर है इसलिए यहाँ पर काम करना अति आवश्यक है |

4. सरकार का बदलना तो बड़ा परिवर्तन है अगर अधिकारी भी बदल जाता है तो शिकायत या मुद्दा भी नये सिरे से शुरू हो जाता है |

हम कैसे कैसे आगे बढे

- 2008 सितम्बर से मंच ने जब समुदाय में शून्य से काम शुरू किया | हमने खुले आसमान के निचे से इस काम की शुरुवात की | लोगों का रवैया सहयोगी नहीं था लोगों के उलाहने मिलते थे | जिसे हमें बदला भलस्वा में लोगों का विश्वास जीता और लोग जुड़ने लगे |
- संसाधनों की कमी होने की वजह से बाहर निकलना संभव नही था | इसलिए हमने समुदाय में काम करते हुए अपनी पहचान बनाई | लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख कर ही काम शुरू किया |

- भलस्वा के लोगों को राशन कार्ड के मुद्दे से RTI को जोड़ा और लोगों को सिखाया |
- मूलभूत सुविधा बिजली को लेकर 700 घरों को रोशन किया | 2009 के अंत तक लोगों का भरोसा मंच पर बढा |

2010 में काम की स्थिति

- 2010 आने तक हमने भलस्वा से बाहर निकलने लगे हमने भलस्वा के अनुभवों को अपने आस पास के समुदाओं में बाटना शुरू किया |
- भलस्वा में राशन के अलावा अन्य मुद्दे शिक्षा, पानी और साफ़-सफाई पर जोर देना शुरू किया |
- समुदाय के इन मुद्दों के साथ घर लाइसेंस के मुद्दे को समझाना शुरू किया जो अन्य मुद्दों के साथ समझना सहज हो रहा था |
- विभागों में शिकायतें भेजनी शुरू की |
- कॉमन वेल्थ गेम जैसे मेगा इवेंट के सामने अपनी समस्याओं को रखा जिससे मंच की पहचान मिडिया में बढ़ी |

2011 - 2012 में

- शिकायतों व मुद्दों पर RTI प्रयोग करना भी शुरू किया |
- उपरोक्त मुद्दों की रोजमर्रा पर काम करते हुए हमने case transfer जैसी जन विरोधी योजना को रोकने में सफल हुए |
- आवास के मुद्दे पर हम जहाँगीर पुरी की झोपडी बस्तियों में भी काम करने लगे |
- अब कॉलेजों से कुछ विद्यार्थी भी जुड़ने लगे थे |
- इसी समय हम इन विधार्थियों के साथ कर्णछपरा और अलवर जैसे जगहों पर भी पहुँच गए |

2012 से 2014 तक

- 2014 तक समस्याओं पर चोट करना शुरू हुआ | लेकिन एक स्थिति यह थी की हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाय | चूँकि हमने विभाग के निचले अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी तक चिठ्ठीयां लिखी, मीटिंग की और इस विभाग से उस विभाग गए लेकिन समस्या का हल नहीं निकल रहा था | तभी हम समझ पाए यह पोलिसी मेटर है इसके लिए और भी तरीके अपनाने पड़ेंगे |
- हमने DRTI (दिल्ली सूचना का अधिकार)और PGC (जन शिकायत आयोग) को भी अपनी शिकायतें करनी शुरू की |

2014 से 2015 तक

- इस समय मुख्य रूप से समुदाय का पानी, साफ़-सफाई और शिक्षा के मुद्दे पर DRTI और PGC का प्रयोग कर रहे है | PGC के पास ही ऐसी शक्तियां है जो विभाग के अधिकारीयों hearing में बुला सकते है और निर्देश देकर काम करवा सकते है | लेकिन PGC जाने से पहले शिकायत कर्ताओं को शिकायत करने की सारी प्रक्रिया को पूरा करना होता है |

नोट - इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पूरी रिपोर्ट को देखना होगा |

रिपोर्ट 2008 सितम्बर से अगस्त 2009 (भाग -1)

1 **मंच की भलस्वा में पहचान बनाना**

घर घर लोग से बात करना , नुक्कड़ मीटिंग करना , बड़ी मीटिंग करना, लोगो की समस्या को समझा और लोगों में अपनी पहचान बनानी शुरू की |

राशन / मिट्टी का तेल

1. राशन के मुद्दे पर लोगों को जागरुक किया |
2. लोगों के साथ दुकानों का विजिट किया |
3. राशन दुकानदारों के साथ बैठकें जिससे दुकानदार और ग्राहक के बीच समन्वय हो सके |
4. राशन की धांधली से लोगो को निपटना आया | अब लोग अपना राशन पूरा और उचित दर पर लेकर आने लगे | यही नहीं लोगों ने दूसरों की मदद भी करनी शुरू की
5. 114 लोगों की मिट्टी तेल नहीं मिलाने की शिकयतें लिखी |

बिजली

1. बिना बिजली के घरों की सूचि बनाई |
2. निजी कम्पनी NDPL(नई दिल्ली पावर लिमिटेड) और लोकल नेता (MLA) के साथ मिलकर 3600 रुपये मीटर लगाने की भारी रकम को कम कर मीटर को 900 रूपये किया गया और 7 कैंप का आयोजन किया गया जिसमे लोगों ने तुरंत पैसा जमा कर हाथों हाथ 600 परिवारों में बिजली के मीटर लगाये गये |

पानी और साफ़ सफाई

1. लोगों के अनुसार और RTI से मिली सुचना के अनुसार हमने पानी और साफ़ सफाई को लेकर विभागों और लोकल नेताओं के साथ पत्राचार शुरू किया |
2. साफ़ सफाई को लेकर लोकल कर्मचारी, अधिकारी के साथ पब्लिक मीटिग करनी शुरू की |
3. मलेरिया विभाग को भी पकड़ा और क्षेत्र में दवाई का छिडकाव और धुआं करवाना |

सुचना का अधिकार का प्रयोग

- मंच ने RTI को हथियार की तरह इस्तमाल किया है भलस्वा के मुद्दों को समझने के लिए RTI से सूचनाये निकली | जिससे हमें अन्य मुद्दों को समझने में आसानी हुई |
- 2009 में राशन कार्ड का नवीनीकारन के बाद कार्ड वापस आने थे लेकिन बहुत से BPL कार्ड केंसल कर दिए जिससे भलस्वा के लोगों के कार्ड भी केंसल हो गए लोगों की बैचेनी व परेशानी को देखते हुए लोगों को RTI के बारे में समझाया और सीखाया गया और 300 से भी अधिक लोगो (अधिकांश महिलाएं) ने RTI का महत्व को समझते हुए RTI फ़ाइल की |

रिपोर्ट

2010 फरवरी से जनवरी 2011 (भाग - 2)

पिछले कार्य को लगातार आगे बढाया | साथ ही भलस्वा में मिली सफलता को भलस्वा से बाहर आस पास के क्षेत्रों कलंदर कालोनी, बसंत दादा पाटिल नगर, विश्वनाथपुरी, जहांगीरपुरी और होलम्बी कलां आदि क्षेत्रो में भलस्वा के अनुभवों को फैलाया और काम किया |

<u>राशन / मिट्टी का तेल</u>

1. राशन वितरण प्रणाली में जो खामिया थी उस पर कार्यवाही की गई उससे बस्ती के 50 - 60 फीसदी लोगों को फायदा मिला |
2. 140 लोगों का राशन कार्ड राशन दफ्तर से निकलवाये | 98 राशनकार्ड के फार्म भरवाए जिसमे से 52 राशन कार्ड बनकर भी आ चुके थे |

3. 114 में से 63 लोगों के राशन कार्ड में मिट्टी तेल चढ़वाया, जोकि डेढ़ साल लम्बी प्रक्रिया थी जिसमे चिठ्ठियाँ, रिमांडर, RTI फिर RTI का नॉन कम्प्लायन फ़ाइल किया गया तब कही. कार्ड का वैरीफिकेशन आदि शामिल है |
4. अनायास ही राशन कार्ड का कैंसल होने से 300 से भी अधिक लोगों ने राशन दफ्तर में जाकर राशन कार्ड नहीं तो बोट नहीं की बात की, जिस पर अधिकारी दफ्तर से ही चले गए लेकिन इसके दबाव से दफ्तर में काम होने लगा |
5. बायोमेट्रिक पर हो रही धांधली में हस्तक्षेप किया जिसमे हो रही धांधली जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्कल में बदलाव, मुखिया का बदलाव, नये नाम जोड़ना और हटाना आदि मुद्दों पर काम पर किया और बायोमेट्रिक की की धांधली को उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाया | HRLN (human right low network)के साथ मिल कर PIL (public interest letigation)फ़ाइल किया गया |
6. अंगूठा टेकने वाली महिलाओ द्वारा डाली गई RTI से सर्कल दफ्तर से लेकर मुख्य दफ्तर तक हडकम्प मच गया जिसमे उलटे सीधे जबाब आने लगे जिससे अधिकारी अपने जाल में स्वयं ही फस गए इसकी वजह से FSO को सस्पेंड किया गया |
7. फाइल की गई RTI से 46 फीसदी कार्ड बने ये वह कार्ड थे जो शायद बनते ही नहीं सिर्फ RTI की वजह से ही बने |
8. महत्वपूर्ण बात यह की भलस्वा में लोगों ने RTI को सीखा जिसका फायदा यह की आज लोग अपनी जरूरत के अनुसार RTI का इस्तमाल कर रहे है |

<u>अन्य बस्तियों में</u>

भलस्वा के राशन के सकारात्मक अनुभव की जरूरत अन्य बस्तियों (होलम्बी कलां, कलंदर कोलनी, बसंत दादा पाटिल नगर, विश्वनाथपुरी और जहांगीरपुरी आदि) को भी थी हमने अपनी क्षमता के अनुसार इन बस्तियों में राशन के मुद्दे पर काम किया |

<u>होलम्बी कलां पुनर्वास कॉलोनी</u>

1. होलम्बी कलां में बड़ी मीटिग की गई जिसमे 600 से 700 लोग जुड़े जिसमे लोगो ने राशन की दिक्कत के साथ साथ साफ़ सफाई की समस्या को बताया |
2. लोकल यूथ और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर समूह के रूप में काम करना सिखाया |
3. राशन कम मिलने की शिकायतों को लेकर होलम्बी कलां में 240 लोगों की शिकायत लिखी गयी जिससे दुकानों में हडकंप मचा जिसका फायदा सभी लोगों को हुआ सभी को पूरा राशन मिलने लगा |
4. जनसुनवाई की जिसमे 600 से 700 लोगों की भागीदारी रही जिसमे भले ही अधिकारी ना पहुचे हो लेकिन लोगों ने राशन व्यवस्था को समझा और आगे बढ़ने का फैसला किया |
5. होलम्बी में भी राशन कार्ड को लेकर RTI कैंप लगाए |

<u>भलस्वा के आस पास के क्षेत्र (जहांगीरपुरी, कलंदर कॉलोनी, विश्नाथपुरी,बसंत दादा पाटिल नगर)</u>

1. स्थानीय लोगों के साथ दुकानों का विजिट किया जिसे लोग में आत्मविश्वास आया लोग दुकानदार से हक़ की बात करने लगे |
2. भलस्वा के बाद यहाँ भी RTI कैंप लगाये गए जहाँगीर पुरी में 86 लोगों ने RTI फ़ाइल् हुई |
3. कम राशन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई और कम राशन मिलने की 653 लोगों की शिकायते लिखी गयी जिसे विभाग ने लेने से भी मना कर दिया जिसे डाक द्वारा भेजा गया जिसकी वजह से हमें धमकियां भी मिली लेकिन तब लोग जागरूक हो चुके थे और लोगों दुकानदार को अपना हक़ के बारे में जागरूक होने लगे थे |

<u>कंट्रोल रूम और RTI की धारा 4 लागू करो</u>

यह दोनों महत्वपूर्ण अंग थे | यही दोनों हिस्से काम नहीं कर रहे थे | पहला कंट्रोल रूम एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर उपभोक्ता कभी भी राशन से सम्बन्धित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते है | दूसरी RTI एक्ट की महत्वपूर्ण धारा 4 को लागू नहीं किया गया था इसके लागू होने से भ्रष्टाचार की सम्भावना खत्म सी हो जाती है क्योंकि ऐसी सूचनाएं जिसकी उपभोक्ता को जरूरत होती है जैसे कितना राशन, कितनी कीमत आदि और इन्ही जानकारियों के नहीं होने की वजह से ही दूकानदार राशन की खूब कलाबाजारी करते थे | इसलिए हमारी कोशिश रही कि ये बोर्ड दुकानों पर लगे होने चाहिए | जिसके लिए विभाग पर पत्रों द्वारा दबाव बनाना शुरू किया |

<u>शिक्षा</u>

शिक्षा का महत्व और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस मुद्दे पर भी शुरुआत की गई जिसमे समुदाय के बच्चों और अभिभावकों के साथ बैठकें की गई जिसमे बहुत सी समस्याए निकली ठीक से स्कूलों की व्यवस्था का नहीं होना, बैठने की सुविधाओं का अभाव, मध्यान भोजन में खराबी, पीने का पानी का नहीं होना, शोचालयों का अभाव गंदगी आदि इनमे सबसे ज्यादा लड़कियों को शौचालयों की दिक्कत थी जिसकी वजह खुले में जाना होता था इसी वजह से छेडछाड की घटनाएं बढ़ रही थी ऐसी स्थिति में बच्चों के अधिकार और मास्टर प्लान को देखते हुए इस मुद्दे पर काम शुरू हुआ |

1. **<u>समुदाय और अन्य संगठनों के साथ बैठकें</u> -** समुदाय **में** गोपनीय योजना बनाई गई कि सबसे पहले स्कूल में शौचालय का मुद्दा उठायेंगें इसके लिए अचानक समुदाय के लोग, अन्य संगठन, पत्रकार सभी एक साथ स्कूल में प्रवेश करेंगे |
2. **<u>स्कूल में शौचालय</u>** - 300 लोगों का समूह एक साथ स्कूल में घुसा देख कर स्कूल प्रशासन घबरा गया लोगों की भीड़ देखकर पुलिस की धमकी मिली लोगों ने जम कर सवाल जबाब किये लड़कियों के लिए शौचालय क्यों नहीं है ? प्रिंसिपल आग बबूला थी इसके बाद स्कूल में भलस्वा के बच्चों को सजा भी दी गई | इसके बाद भी महिलाए स्कूल जाकर बात करती रही और RTI डाल कर स्कूल की नाक में दम कर दिया स्कूल के वजट का फाइल निरिक्षण किया | अंतः स्कूल में **10 नये शौचालयों का निर्माण** हुआ |
3. **<u>छात्रों (विशेष लडकियां) की सुरक्षा</u> -** भलस्वा से स्कूल की दूरी 1 से 2 किलोमीटर होगी जो सुनसान रास्ता था जिसमे कई घटनाएँ छेड़छाड़ और अपहरण की सामने आई | इसे देखते हुए स्कूल प्रशासन को बात की और नजदीकी पुलिस थाने को भी बात की | पुलिस ने टालामटोली पर महिलाओं के समूह ने पुलिस को ठीक से पाठ पढ़ाया अंतः छात्रों की सुरक्षा के लिए PCR का प्रबंध किया गया |
4. **<u>शिक्षा अधिकार मंच के साथ जुड़ाव</u>** - जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण और व्यपार चल रहा है हालाकि हर जगह पर लोग संघर्ष कर रहे है इसके बावजूद पूरी व्यवस्था से लड़ना आसान नहीं इसलिए नेटवर्क में काम करना जरुरी है इसी के तहत मंच शिक्षा अधिकार मंच के साथ जुडाव हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था में चोट करने की कोशिश शुरू की | जिसमे समुदाय के लोगों ने अपनी बेहतर भूमिका निभाई |

<u>साफ़ सफाई</u>

1. महिलाओं ने इस मुद्दे पर समझ बना कर सफाई कमचारियों के मीटिंग की और समुदाय में सफाई के काम को स्वम् मोनिटर करने लगी | सफाई कर्मचारी के साथ विजिट करना और सफाई करवाना आदि |

2. भलस्वा की बेहतर काम को देखते हुए महिलाओं ने यही मन्त्र पास के समुदाय कलंदर कॉलोनी, विश्वनाथपुरी और बसंत दादा पाटिल नगर को भी दिया | लोगों को जागरूक किया | लोगो के हस्ताक्षर के साथ DC को शिकायत पत्र लिखा गया | अधिकारीयों ने समुदाय में विजिट किया | शिकायत करने से कुछ नहीं होता कहने वाले लगभग 500 लोगों ने अधिकारीयों के साथ अपने क्षेत्र का दौरा करवाया और सफाई कर्मचारियों की पोल खोली केसे कर्मचारी समुदाय से पैसा लेते है और कामचोरी करते है | इस प्रक्रिया के बाद इन समुदायों से वर्षों का कूड़ा लोडरों से उठा |

3. **<u>होलम्बी कलां</u>** भी एक पुनर्वास कॉलोनी है यहाँ की स्थिति भी भलस्वा से भी भयंकर थी |शोचालयों का पानी घरों के अंदर घुस रहा था | यहाँ भी लोगों को जागरूक किया गया | लोगों को साथ जोड़कर यहाँ भी कार्यवाही को आगे बढाया गया | 300 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया | और इस प्रक्रिया को आगे बढाया गया |

<u>आवास</u>

गाँवों में भुखमरी के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहरों में खींचे आते है | कुछ लोग लौट जाते है और कुछ यहीं के होकर ही रह जाते है | शहर में लोगों की भूख पर कुछ नियंत्रण तो हो जाता है लेकिन आवास अर्थात एक छत जिसे वो अपना कह सके, उसकी व्यवस्था करना आसान नहीं होता | इसलिए लोगों ने काम की जगहों पर झोपडी डालकर ही जीना शुरू कर दिया | शहरों में एक बड़ा वर्ग इन बस्तियों में ही गुजर बसर करता है | देश की राजनीति में इनका खूब इस्तमाल होता है और बदले में इन बस्तियों को मिलता है विस्थापन का दर्द जिसका जीता जगता उदाहरण है भलस्वा |

सन 2000 से 2002 तक लोगों 11 झोपड़ी बस्तियों उजाड़कर भलस्वा में पटका गया | भलस्वा यमुना का किनारा है जमीन दलदली और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में आती है फिर भी लोगों को यहाँ पटका गया | घर के नाम पर 7000 रुपयों के बदले लोगों को मिला 18 वर्ग मीटर और 12.5 वर्ग मीटर का जमीन का टुकड़ा, जिसे 10 साल के लाइसेंस पर दिया | भोलेभाले मेहनतकश अक्षर ज्ञान नहीं रखने के कारण इस जानकारी से अनभिज्ञ ही रहे और यहाँ पर छत बनाने के लिए लोगों ने पूरे जीवन की मेहनत की कमाई लगा दिया या फिर कर्जा लिया, गाँव की जमीन को बेचा आदि | लेकिन 10 साल के बाद क्या ?

यह बहुत ही नाजुक मुद्दा था जिसे लोगों को सीधे बताने से लोगों की साँसे थम जाती है कई बार तो लोगों बहुत दुखी हो जाते यहाँ तक की टेंशन में आकर तबियत खराब हो जाती ऐसे में हमने लोगों को उनकी रोजमर्रा की जरूरत के मुद्दों पर काम कर विश्वास बनाया और धीरे धीरे इस मुद्दे को हर मीटिंग में, बातचीत में लोगों को बताना शुरू किया इसके बाद लोगों ने समझना शुरू किया और इससे निपटने के लिए जानकारी लेनी शुरू की |

हमने RTI से और विभाग के साथ बैठकों में इसी सम्बन्ध में जानकरी भी मांगनी शुरू की | विभाग का जबाब यह की विभाग के पास अभी इससे सम्बन्धी कोई सुचना नहीं है | मौखिक रूप से अधिकारी कहते यह मोबाइल चार्ज की तरह जिसे रिचार्ज कर दिया जाएगा | वेसे भी दिल्ली में कितनी पुरानी पुनर्वास कालोनी है उन्हें कुछ नहीं हुआ तो भलस्वा को भी कुछ नहीं होगा | यदि अधिकारीयों की बात पर विश्वास करें तो दस्तावेज में यह क्यूँ लिखा (यह आपका अस्थाई निवास है) गया ? इसका कोई जबाब नहीं है |

<u>कैंसल प्लाट</u> - भलस्वा में लगभग 4000 परिवार है | जिसमे से 418 घर कैन्सिल है यह सुचना हमें RTI से निकली जिनकी लिस्ट भी हमारे पास आगई | हम इस मुद्दे को लेकर घर घर गए और बातो को घुमा कर पूछना शुरू किया हम जानते थे की यह काम आसान नहीं है | जब यह बात सामने आई कि घर कैन्सिल है तो लोगों की धड़कने बढ़ गई घबराहट होने लगी | लोगों दलालों को पकड़ने लगे और जिन दलालों ने इन घरों को बेचा व खरीदा था, उन लोगों ने मंच को धमकी दी कि हम यह काम छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा | मंच ने इस पर काम किया लोग को तैयार किया की अगर इस पर सरकार का कोई भी एक्शन होगा तो हमें एकत्र होकर संघर्ष करना होगा | लोग अपनी इस लड़ाई के लिए तैयार है | हांलाकि अभी इस सम्बन्ध में विभाग की और से कोई जानकारी नहीं है | इसके साथ साथ हमने लोगों को लाइसेंस को लेकर हर मीटिंग में जागरूक करते है |

<u>प्रतिक्रिया</u> - लोगों ने कहा की पुनर्वास से पहले यह जानकारी उनको नहीं दी गई थी | बस्तियां खाली करवाने के लिए सुंदर सपने दिखाए गए थे उनको क्या पता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है | अगर पहले की बस्तियों में उनके पास यह जानकारी होती तो वे अपनी बस्ती को टूटने भी नहीं देते | लेकिन अब अगर हमारे घरों के साथ कुछ भी हुआ तो वे सड़कों पर उतरेंगे |

<u>कार्यशाला</u> - पुनर्वास नीति और कानून की समझ बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया | कार्यशाला के विशेषज्ञ खतरा केंद्र के दुनु जी थे | जिससे हम नीति और कानून का फर्क समझ पाए |

<u>पानी</u>

यह वह वक्त था जब हम इस मसले को समझ की कोशिश कर रहे थे और समझ भी पाए | दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) और MLA के साथ RTI की सूचनाओं के आधार पर बैठकें शुरू की | जिसके आधर पर यह पूरा मसला समझ में आने लगा था कि इस पूरे मसले को ऐसे उलझा कर रखा था है जिससे कोई भी साधारण इंसान इस व्यवस्था के समस्या का हल तो क्या उसके बारे में समझ भी नहीं सकता | क्योंकि विभाग एक दुसरे के उपर आरोप लगा रहे थे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे थे |

<u>बिजली</u>

जहाँ बिजली के कैंप लगाने से 600 लोगो के घर रोशन हुए वही बिजली के भरी भरकम बिलों से लोग परेशान हो गए | ऐसे में NDPL (नई दिल्ली पावर लिमिटेट) प्राइवेट कम्पनी को लोगों ने 70 चिठ्ठियाँ लिखी गई और लोगों ने प्रदर्शन किया | जिससे मीटर फ्री में चेक हुए और बिलों में भी राहत मिली |

<u>अन्य</u>

मंच का काम ढांचा लचीला है इसलिए लोग के जरूरतों और स्थिति पर ही काम करता है निम्न कार्यक्रम अकस्मात ही सामने आये जिस पर हमने काम किया और सफलता भी पाई |

<u>भलस्वा में बाढ़</u> - बिना योजना के बसाया गया भलस्वा यमुना के किनारे दलदली जमीन में बसाया गया है जिसमे सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर टूटता है बाढ़ आने से भलस्वा चारों और से पानी में घिर गया सारे रास्ते टूट गए 3 जानें भी चली गई | इस पर लोगों को संगठित कर 70 लोगों ने DUSIB के दफ्तर में जाकर अधिकारीयों के साथ मीटिंग की | पूरे क्षेत्र का दौरा करवाया और 2 पम्प 2 महीने तक अपनी निगरानी में चलवाए तब कही भलस्वा को बाढ़ के पानी से राहत दिलवाई |

<u>कॉमन वेल्थ गेम्स के विरुद्ध कार्यक्रम</u> - जिस देश में भूखमरी हो और लोग बेघर हो उस देश में कॉमन वेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया हो | इन खेलों को लेकर शहर में अंधाधुंध विस्थापन चल रहा हो लोगो को शहर से बाहर खदेड़ा जा रहा हो और लोग को राशन कार्ड से वंचित भी किया गया हो | दिल्ली में 1 लाख 70 हजार BPL कार्ड निरस्त का दिए गए साथ ही यह ऐलान भी खेलों के दौरान को मजदूरी करने भी शहर में कोई नहीं निकलेगा | इससे लोग आहत थे | ऐसे में दिल्ली नेटवर्क में लोग एकत्र हुए और दिल्ली को एक दिन के लिए चक्का जाम तय किया जाय तय हुआ |
जिन 6 जगहों को चिन्हित किया गया जिसमे भलस्वा क्रोसिंग भी एक था दिल्ली के पांच जगहों साधारण पर्चा बाटा गया और दिल्ली विश्वविद्याल में जलूस निकाल कर इसे समाप्त कर दिया गया लेकिन भलस्वा के लोगों ने 40 मिनट तक चक्का जाम रखा पुलिस का लाठी चार्ज हुआ महिलाओं को चोटें लगी कुछ युवाओं को पुलिस पकड़ा

और जमकर पीटा लेकिन महिलाओं को काबू करने में पुलिस को कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी तब कहीं महिलाओं ने रास्ता छोड़ा |

अंतः सरकार की तानाशाही पर लगाम लग पाया और मजदूर वर्ग इन 10 दिनों में मजदूरी कर के अपने परिवार भरण पोषण कर पाए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी |

रिपोर्ट 2011 दिसम्बर से अगस्त 2012 (भाग - 3)

राशन

जहाँ 60 फीसदी जनता आज भी राशन पर जीती हो और सरकार राशन के बदले पैसे की योजना लेके आये हालाकि लोगो को राशन की जरूरत है ऐसे में राशन व्यवस्था को जिन्दा रखना बहुत ही जरुरी हो जाता है इस वर्ष मंच ने अपनी प्री ताकत इसे रोकने में लगाई जो निम्न प्रकार है |

1. **PDS (राशन वितरण प्रणाली) की जगह cash transfer (राशन के बदले पैसा) योजना**

जैसे ही व्यवस्था में गड़बड़ी के बारे में लोग जागरूक होने लगे और विभाग की खामियों को सामने लाने लगे और व्यवस्था सुधार की बात करने लगे राशन निति को जमीन पर ठीक से लागू करने लगे तभी राशन व्यवस्था को बंद कर राशन के बदले पैसा की योजना को जनता के सामने रखा गया हालाँकि जनता इसका विरोध कर रही बावजूद इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया |

यह योजना दिल्ली के लिए थी इसलिए कोई भी संस्था अकेले इसका विरोध नहीं कर सकती थी इसलिए मंच कुछ नेटवर्क (राशन व्यवस्था सुधार अभियान और right to food रोजी रोटी अभियान दिल्ली) के साथ जुडा और संघर्ष आगे बड़ा जिसके तहत सर्वे हुए जिसके आकड़े बताते है कि 95 फीसदी लोग राशन की मांग कर रहे है इसके बावजूद भी इस मुद्दे पर ठीक से कोई नतीजा नहीं निकल रहा था | हालाँकि विभाग के उपर इसका भारी दबाव था इसे देखते हुए विभाग द्वारा दो और पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी जिसमें जहांगीरपुरी भी शामिल था जिसको लेकर मंच ने अपने स्तर पर कोशिशें शुरू की |

(क) RTI फाइल कर इस योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेज निकाले जो बहुत ही चौकाने वाले थे |
हमने दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर संस्थाओं से बात की अभियानों से भी बात की लेकिन हर किसी ने अपनी मजबूरी बता कर अपना हाथ पीछे खींच लिया तभी मंच ने निर्णय लिया कि वह अपनी क्षमताओं के अनुसार जहांगीरपुरी से ही लोगों के साथ मिलकर काम करेगा |

(ख) विभाग द्वारा जहांगीरपुरी में पब्लिक मीटिग बुलाई गई जिसकी जिसकी सुचना हमें 15 घंटे पहले मिली जिसके लिए रात तक लोगों के साथ चर्चा हुई और बैठक में जाकर अपना सही निर्णय सुनाने के लिए तैयार किया |

(ग) देर रात तक प्ले कार्ड और अन्य तैयारी की गई | बैठक में जाने से पहले लोगों को फोल्ड कर प्ले कार्ड पकड़ा दिए गए लगभग 1000 लोग मीटिंग हाल में बैठे थे, जैसे ही UNDP की तरफ cash transfer के बारे में काल्पनिक भूमिका गढ़ी जा रही थी कि लोगों ने अपना फैसला प्लेकार्ड उठाकर सामने रखा | जिससे पूरी मीटिंग असफल रही और लोगों ने अपनी पहली जीत दर्ज की |

(घ) मंच ने इसे रोकने के लिए कई संगठनो से और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अभियानों से मदद मांगी लेकिन इसमें सभी ने अपने हाथ पीछे खीच लिए | हमने तय किया की अगर हम इसे जहाँगीरपुरी में विफल कर देंगे तो यह पूरी दिल्ली के लिए काम होगा | हमने तीन महीने (अप्रैल से जून तक) भयंकर गर्मी में अभियान चलाया जिसके तहत 11000 पर्चा बाटा | 3000 से अधिक स्टीकर चिपकाये | लगभग 5000 लोगों से हस्ताक्षर करवाए | क्षेत्रीय नेताओं, अधिकारीयों हस्ताक्षरों के चिठ्ठियाँ लिखी |

(च) प्रेस कांफ्रेंस की और प्रशासन के दबाव व जन सुनवाई की इजाजत को रद्द करने के बावजूद जनसुनवाई की इसमें लगभग 600 लोगों की भागीदारी रही |

(छ) case transfer Hold - अंतः सरकार से case transfer को होल्ड करने के लिए मजबूर होई गयी | यह हमारी बड़ी जीत थी | हम राशन व्यवस्था बचा पाए |

2. <u>कंट्रोल रूम को चालू करवाना</u>

खाद्य संभरण विभाग दिल्ली का एक मात्र कंट्रोल रूम जहां पर लिख कर शिकायत करने की जरूरत नहीं केवल फोन से ही शिकायत दर्ज हो सकती है यह समुदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था इसके लिए कमिश्नर और अन्य अधिकारीयों के साथ 5 बैठकें की गई, 30 चिठ्ठियाँ लिखी गई और एक अधिकारी सस्पेंड हुआ इसके बाद इसे चालू किया गया जो की महत्वपूर्ण सफलता थी |

3. <u>RTI की धारा 4 को लागू करना</u>

CIC के इस आदेश को लागू करवाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा | जिसके लिए अधिकारीयों के साथ 20 - 25 मीटिंग की गई और 454 चिठ्ठियाँ लिखी गई | तब कही हम सर्कल 5 में इसे लागू पाए |

4. <u>नागरिक अधिकार पत्र आदेश की खामिया सुधार की प्रक्रिया</u>

अंगेजी में छपे इस सिटिजन चार्टर को आम लोगो की भाषा में किया जाय और गलत नम्बरों ठीक किया जाय जिससे इसका इस्तमाल आम लोग कर सके इसके लिए 78 चिठ्ठियाँ लिखी गई और 12 मीटिंग हुई तब कहीं यह सिटिजन चार्टर को ठीक हुआ |

5. <u>विभाग में जन अदालत की शुरुआत</u>

जहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हो तो उनकी समस्या विभाग तक नहीं पहुँचती जिससे विभाग के पास काम नहीं करने के बहाने होते है | इसके लिए कमिश्नर के साथ मीटिंगें हुई और आदेश जारी करवाया गया सप्ताह में एक दिन सह आयुक्त के दफ्तर में जन अदालत होगी जिसमे लोग अपनी समस्या का निराकरण कर सकें |

6. <u>वरिष्ठ अधिकारीयों की ईमेल ID विभाग के वेबसाइड पर डलवाना</u>

यह भी महत्वपूर्ण कार्य था जिसके होने से वेबसाइड इस्तमाल करने वालों के लिए शिकायतें करना आसान हो गया इसके लिए कमिश्नर के साथ मीटिंग के साथ कई बार बैठकें हुई तब विभाग को मजबूर होकर इसे वेबसाइड पर अपडेट करना पड़ा |

7. <u>होलम्बी कलां से सह आयुक्त के दफ्तर में 120 लोगों का हुजूम</u>

यह बड़ी कामयाबी थी दूसरे समुदाय में काम करने की | यहाँ RTI कैंप किये गए बड़ी मीटिंग भी की गई यहाँ के यूथ को जोड़ा गया और जनसुनवाई भी की गई | जनसुनवाई में ही लोगों ने तय किया की वे एकत्र होकर AC के दफ्तर में जायेंगे और बात करेंगे | यही हुआ 120 लोग और भलस्वा के लोग सहयोग के रूप में AC के दफ्तर पहुचे जिन्होंने AC को बाहर बुलाकर अपनी समस्या पर काम करने का वादा लिया | और काम भी हुआ अर्थात लोगों ने सीखा काम कैसे होता है |

पानी

पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं होने की वजह लोगों को भू-जल पीना पड़ रहा था जिसका असर लोग के स्वास्थ्य में दिखाई दे रहा था | स्थिति को देखते हुए निम्न कार्य किये |

1. **भू-जल की जांच** - पानी कितना खराब है इसके लिए पानी जांच जरुरी थी इसलिए खतरा केंद्र के साथ मिलकर भलस्वा और उसके आस पास के क्षेत्रों नंगली पुना मुकुंदपुर और नत्थूपुरा से पानी जाँच के सेम्पल एकत्र किये, जिसकी जांच खतरा केंद्र ने PSI देहरादून करवाई |

2. **स्वास्थ्य सर्वे** - पानी की खराबी लोगों के स्वास्थ्य क्या प्रभाव डाल रही है इसके लिए मंच ने उन्हीं स्थानों से 866 लोगों (परिवार) का स्वास्थ्य सर्वे भी किया | पानी की रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट को मिलकर एक रिपोर्ट तैयार हुई यह कार्य खतरा केन्द्र ने किया |

3. **कार्यशाला** - स्वयं के सीखने के लिए कार्यशाला की | कार्यशाला से मिली जानकारी ने हमें इस संघर्ष में मदद मिली |

4. **प्रेस कांफ्रेंस** - इस रिपोर्ट को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की जिससे यह रिपोर्ट नेताओं व अधिकारीयों तक पहुँच गई | जिसका असर विभागों पर पड़ा | दिल्ली जल बोर्ड ने भलस्वा के सारे हैण्डपम्प पर लाल कलर लगा दिया की यह पानी खतरा है | प्रिंट मिडिया, इलैक्ट्रोनिक मिडिया (दिली आज तक ने सीधा प्रसारण किया और दूरदर्शन ने डोकोमेंन्ट्री बनाई |

5. **MLA को उसके घर में ही पकड़ना** - समुदाय की महिलाओं का समूह सुबह 5 बजे ही MLA को नींद से जगाता | बार बार हमें झूठा ही आश्वासन मिलता | जबकि MLA ने मंच से पूरी फ़ाइल मांगी और हमने पूरी फ़ाइल MLA को दी जिस पर MLA ने फ़ाइल पर लिखा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भलस्वा के लिए महत्वपूर्ण होंगे | इसी दस्तावेजों के आधार पर MLA ने DJB के CEO के साथ मीटिंग हो पाई

6. **DUSIB के दफ्तर में 40 महिलायें** - अधिकारीयों के साथ मीटिंग, और भलस्वा में नयी पाइप लाइन के लिए 14 लाख रुपया मंजूर हुआ |

7. **रिपोर्ट के साथ पत्राचार** - रिपोर्ट को लेकर DJB, DUSIB, CIC, PGC, NHRC,CM आदि के साथ पत्राचार किया जिससे कुछ कार्यवाही तो हुई | PGC ने इस पर hearing करना शुरू किया |

8. **डॉक्टर की टीम का भलस्वा विजिट** - NHRC के दबाव से डॉक्टर की एक टीम ने भलस्वा का विजिट किया इनका कहना था अगर पुनर्वास से पहले हम से पूछा होता तो हम यहाँ पुनेवास की इजाजत नहीं देते क्योंकि यह जगह इंसानों के है नहीं लेकिन मौखिक रूप से तो यह काम आगे नहीं बढ़ सकता था इस पर हमने आगे कार्यवाही की |

9. **PGC की hearihg** - भलस्वा के काम को लेकर मंच क्षेत्रीय नेताओं से लेकर विभागों के सेकड़ों चक्कर लगाए लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था | ऐसे PGC से उमींदे जागने लगी अधिकारियों को

यहाँ पर नोटिस भेजा जाने लगा और दौर शुरू हुआ hearing का | यह हमारे लिए उमींद की किरण बन कर उभरा |

<u>शिक्षा</u>

अगर देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो तो फिर पूरा देश ही प्रगति करने लगेगा | लेकिन इस व्यवस्था का जमकर मजाक उड़ाया गया है सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून बनाकर स्कूली शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है | व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही और बच्चों को जानवरों की तरह स्कूलों में ठूसा गया है जहाँ ना ही पीने का पानी, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था और ना ही बैठने की व्यवस्था है | हमने भलस्वा के आस पास के स्कूलों की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है |

1. **<u>भलस्वा के नजदीकी स्कूल लिबासपुर को 12वीं तक करवाया</u>** - आस पास और कोई स्कूल नहीं होने की वजह से ख़ास तौर पर लडकियाँ पढ़ाई से वंचित हो जाती थी | इसके लिए विभाग के साथ मीटिंग की गई हस्ताक्षर अभियान चलाया और पत्राचार किया गया जिसके दबाव से हमने स्कूल को 12वीं तक करवाया |

2. **<u>पीने के पानी की व्यवस्था</u>** - भलस्वा के प्राइमरी स्कूलों में बच्चो के पीने के पानी नहीं थी फिहाल हमने अस्थाई पानी की व्यवस्था की टेंकर से और RO की व्यवस्था के लिए पत्राचार चल रहा है |

3. **<u>स्कूल निर्माण का प्रयास</u>** - मास्टर प्लान (कानून) के मध्यनजर भलस्वा में स्कूल की बहुत कमी है जिसको लेकर पब्लिक मीटिंग की गई और लोगो के साथ शिकायत अभियान चलाया जिसके तहत लगभग 1866 लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें लिखी गई और समुदाय से लोगों का एक बड़ा समूह शिक्षा निदेशक के पास पहुंचा और शिकायतें फ़ाइल की | आदेश हुआ की जगह चिन्हित की जाय |

4. **<u>स्कूल के लिए अधिकारियो के साथ समुदाय का दौरा</u>** - भलस्वा ले-आउट प्लान में चिन्हित जगहों देखा गया और जमीन पर भी चिन्हित किया गया | आगे के कार्यवाही के लिए **RTI का प्रयोग** किया गया |

आवास

महानगरों में विस्थापन और पुनर्वास आम प्रक्रिया बन गई है जिसका कहर हमेशा मेहनतकशों मजदूर वर्ग के उपर पड़ता है | लेकिन इस समय पुनर्वास नीति बदल दि गई है | वजह है दिल्ली में जगह नहीं है जबकि खतरा केंद्र के शोध के अनुसार आज की स्थिति में भी दिल्ली में इतनी जमीन है हर परिवार को 50 वर्ग मीटर जमीन मिल सकती है | इसके बावजूद भी बदलाव यह कि लोगों को प्लाट अलोटमेंट की जगह फ्लेट योजना ने जगह ले ली है |जिसके तहत अभी भलस्वा में 7400 फ्लेट्स बनाने का काम शुरू हो गया है | भलस्वा में पुनर्वास को लेकर आगामी योजना क्या होगी कुछ कहना संभव नहीं है | फिरहाल तत्कालीन शीला दीक्षित की सरकार ने 35 से 40 साल पुरानी पुनर्वास कालोनियों को मालिकाना हक के लिए सर्कल रेट तय कर किया | यह रेट लोगों की क्षमताओं से बाहर है | जो इसे नहीं दे पायेगा उसे अपना घर छोड़ना होगा इसलिए इस संघर्ष का स्तर एक बस्ती से नहीं हो सकता जिसके लिए अन्य लोगों को भी संघर्ष में शामिल करना होगा इसके लिए मंच प्रयासरत है | हमने निम्न कार्यों की शुरुवात की |

1. **कार्यशाला**

आवास अधिकार और विस्थापन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया यह कार्यशाला में भी दुनु राय जी द्वारा जानकारी दी गई | जिसमे विशेष बात यह निकल कर आई अगर सरकार की जन विरोधी योजना का विरोध करना है तो हमारे पास भी सरकार की तरह आकड़े होने चाहिए क्योंकि सरकारें हमेशा आकड़ों से ही मात देती है | अंतः कह यह तय हुआ की भलस्वा में हम सर्वे करेंगे |

2. **भलस्वा में लैंड सर्वे**

हमने खतरा केंद्र के सहयोग से सर्वे फोर्मेट तैयार किया और इसे करना शुरू किया | हमारे पास सर्वे टीम नहीं होने की वजह से हम से इस साल पूरा नहीं कर पाए अर्थात हमने सर्वे शुरू किया |

3. **एक्सपोजर विजिट**

देश के अन्य राज्यों में आवासीय क्या स्थिति है | यह जानना भी हमारे लिए जरुरी था | खतरा केंद्र के सलाह से हम छत्तीसगढ़ राज्य के एक्सपोजर पर गए |यहाँ का अनुभव बहुत ही प्रेरणादायक रहा जिससे काम में ताजगी और नये आडियाज मिले |

4. **भलस्वा के आस पास की झोपड़ी बस्तियों में जागरूकता**

जहांगीरपुरी, कलंदर कलोनी, विश्वनाथपुरी, बसंत दादा पाटिल नगर में नुक्कड़ मीटिंग की और परचा बांटा | इन बस्तियों में भलस्वा पुनर्वास के कड़वे अनुभवों को बाटा | जिससे लोगों पुनर्वास होने से पहले समझ बना ले, कि पुनर्वास जरुरी है भी की नहीं | अगर जरुरी है भी तो पुनर्वास कैसा हो, लोग स्वयं जाकर देखे तभी तय करें जाना भी है की नहीं |

5. **नेटवर्क के तहत मंत्रालय HOOPA के साथ बैठक**

खतरा केंद्र और अन्य संगठन के साथ इस मंत्रालय में बैठक हुई जिससे यह स्पष्ट हो गया की लोगों की राय मंत्रालयों के लिये कोई माइने नहीं रखती | आकड़ों और जनता की ताकत की जरूरत दिखाई दी | इसलिय हमारी ताकत लोगों को समझाने में ही लगती है |

अन्य

1. **भलस्वा में सड़कें और गलियाँ**

भलस्वा बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बसाया गया है | यह मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है | भलस्वा जब बसा तब से यह अपना दम तोड़ चुकी थी जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतों (लोगो का गिर जाना रिक्शा का पलट जाना आदि) का सामना करना पड़ रहा था |

भलस्वा की गलियों का जिग्र करें तो गलियों का खडंजा अपनी 5 साल की उम्र तय करके जबरदस्ती जी रहा है जिसके लिए भी हमने काम किया |

- MLA के साथ बैठके और पत्रचार किया गया जिससे दबाव बना
- सूचना का अधिकार पूरी तरह इस्तमाल किया | जिससे सड़कों के बारे में चौकाने वाली सूचनाये मिली यह छोटी सी सड़क कई विभागों के पास में थी जिसकी वजह से काम कर पाना आसान नहीं हो रहा था | RTI से काम करने में दिशा मिली |
- RTI के तहत सड़क के मसले को लेकर CIC जाना पड़ा जिससे विभागों के उपर दबाव बना | और सड़क बनने का काम शुरू हुआ |
- RTI से ही गलियों के कार्य करने में मदद मिली | विभाग से सही सूचना नहीं मिलने की वजह से विभाग स्वयं ही उलझता चला गया |
- महिलाओं के समूहों ने विभाग में जाकर अधिकारियो पर दबाव बनाया और भलस्वा में RCC (कंकरीट) की मंजूरी मिली |

कार्यक्रम

1. **जागरूकता कार्यक्रम**

अलग अलग बस्तियों में काम करना उनको एक जगह लाकर काम की शेयरिंग करना और लोगों को जोड़ना ही इस कार्यक्रम का उदेश्य था जिसमे गीत , नाटक , अनुभव शेयरिंग और सहभोज का कार्यक्रम था | क्षेत्र का निगम पार्षद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों के साथ सवाल जबाब हुए | 700 से 800 लोगों की भागीदारी रही, 11 संगठनों ने भी अपनी भागीदारी दी | इस कार्यक्रम में लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया गया |

2. **भलस्वा कार्यक्रम का रिब्यु**

मंच ने जब से कार्य करना शुरू किया | काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं इसके लिए दो दिन का रिब्यु कार्यक्रम रखा गया | मुख्यतः मंच और टीम का व्यक्तिगत यह मूल्यांकन था | जिसके रिसोर्स प्रशन दुनु राय और डॉ इमराना थे | जिससे यह कुछ कमजोरियां समझ में आयी | अधिकारों की लड़ाई में रोजगार की लड़ाई को भी शामिल करना चाहिए |

3. **अलवर राजस्थान में RTI और युवाओं की सोच पर ट्रेनिग कार्यक्रम**

अलवर के छात्रो के अनुरोध पर यह ट्रेनिग कार्यक्रम रखा गया जिसमे 25 से 30 गाँव के 38 छात्रों ने भाग लिया जिसमे उनके गाँव की दिक्कतों में RTI कैसे काम कर सकता है जानकारी दी गई और RTI के बारे में सीखाया | इसका मकसद व्यवस्थाओं में युवाओं की भूमिका बढ़ाना था |

4. **सुचना का अधिकार एक हथियार**

जिस तरह से हमारे संघर्ष में RTI हथियार साबित हुआ है हम इसका भरपूर इस्तमाल करते है | इसकी महत्वता को समझते हुए ही हमने समुदाय में 300 से अधिक लोगो को सीखाया है | राशन, पानी, साफ़ सफाई, शिक्षा, गली

सड़क, आवास आदि पर भी 50 से 55 RTI डाल कर विभागों पर दबाव बना कर काम किया है | यही नहीं समुदाय में भी लग अपनी जरूरत के अनुसार इसका इस्तमाल करते है |

<u>खानपुर में महिलाओं के साथ स्वास्थ्य की प्रारम्भिक जानकारी पर ट्रेनिग</u>

इस ट्रेनिग में 18 महिलायें शामिल हुई इसका आयोजन महिला कल्पना शक्ति ने किया | महिलाए जहाँ घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी सम्भाल रही है और पूरे परिवार का ध्यान रखती वही वे अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं होती जिससे उनका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है | ट्रेनिंग में महिलाओं की शारीरिक दिक्कतों पर चर्चा करते हुए महिलाओं के खान पान की बात हुई | महिलाओं ने इस कार्यशाला को सराहा और कहा वे पहली बार ही अपने बारे बात कर पाई जो उन्हें अच्छा लगा |

रिपोर्ट 2012 सितम्बर से 2014 फरवरी (भाग -4)

राशन

राजधानी दिल्ली की तस्वीर को गरीब मुक्त शहर के रूऊ में दिखाई जा रहा है हकीकत इससे अलग है | गाँवों से लगातार लोगों को रोजगार की तलाश दिल्ली में पलायन के लिए मजबूर कर रही है ऐसे में राशन और राशन की दुकानो का क्या क्या महत्व हो सकता है यह समझा जा सकता है | जिस तरह से जनसुविधाओं का नीजिकरण और पूंजीवाद को बढ़वा दिया जा रहा है | ऐसे में राशन व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है |कभी **case transfer** को तो कभी अन्नश्री योजना को लाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और अब खाद्य सुरक्षा बिल जिसमे बहुत सी खामियां है |

महत्वपूर्ण यह भी है जैसे ही हम भलस्वा में PDS को लेकर लोगों को जागरूक कर पाए | लोग अपनी समस्या का हल स्वयं करने लगे थे | वैसे ही नया खाद्य सुरक्षा बिल को लोगो के सामने रख दिया गया जिसके लिए नये सिरे से लोगों को समझाना शुरू किया | इस बदलाव को देखते हुए मंच ने दो प्रकार से काम किया है |

1. नये खाद्य सुरक्षा बिल के बारे लोग को जानकारी देना और जागरूक करने की कोशिश की |
2. पिछले कार्यो के अनुभवों को अन्य लोगों व संस्थाओं के साथ बांटना भी शुरू किया |

अन्न श्री योजना

case transfer के फेल होने के बाद तुरंत किसी नोटिस के अन्न श्री योजना को शुरू कर दिय्स गया | जहां **case transfer** में BPL कार्ड धारी को 1000 रूपये देने की बात थी वही अब APL कार्ड धारी जिन्हें राशन नहीं मिलता था उन्हें 600 रुपया दिया जाने लगा | यह योजना पूरी तरह से राजनीति (चुनाव) से प्रेरित थी | भलस्वा की महिलाओं ने अन्न श्री का GRC के दफ्तर में जाकर इसे वापस लो की मांग की | अंतः यह योजना भी पूरी दिल्ली में विफल रही |

अन्न श्री के नाम पर रिश्वत चली तो लोगों ने किया हंगामा

इस योजना के नाम कुछ दलालों ने समुदाय में विधवा महिलाओं को बेवकूफ बनाना शुरू किया और उनसे 300 - 300 रूपये लुटने शुरू किये | भलस्वा में महिलाए एकत्र हो गई और दलालों से उनकी ID मांगी और कहा वे बताएं उन्हें कौन से अधिकारी ने भेजा है | पड़ताल करने पर पता चला की इन लोगों को सर्कल इंस्पेक्टर ने भेजा है | महिलाओं ने लिखित शिकायत की और इंस्पेक्टर ने ने सार्व्जनिका रूप से माफ़ी मांगी | यह घटना यह संकेत करती है लोग अपने अधिकार के लिय जागरूक हो रहे है |

जहांगीरपुरी में तीन राशन दुकान का बंद होने पर संघर्ष

तीन दुकानों के बंद होने से लगभग 3000 परिवार प्रभावित हो गए | जिसके 2 बड़ी पब्लिक मीटिंग की जिसमे 150 से 300 लोग शामिल हुए लोग का समूह सर्कल-4 तक पहुँच गया | कमिशनर को चिठ्ठियाँ लिखी | दबाव से 2 महीने से बंद दुकानों के कार्ड लोदुसरी दुकानों पर भेजे गए और लोगों का 2 महीने का राशन एक साथ मिला | लोगों के संघर्ष से बंद राशन दुकानों को जल्दी ही खोल दिया |

APL राशन कार्डों पर अचानक राशन बंद

2 पब्लिक मीटिंग की जिसमे 200 से 300 लोग एकत्र हुए लोगों ने हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी ली | 543 हस्ताक्षर हुए और 39 लोगों ने व्यतिगत शिकायतें लिखी | समुदाय से महिलाओं का समूह मुख्य दफ्तर (H Q) ITO कमिशनर से मिले और शिकायत दर्ज करवाई | इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष यह निकला कि राशन चालु हुआ यही नहीं पिछले दो महीने का रुका राशन भी मिला |

रसोई गैस के लिए आवेदन भरवाने

दिल्ली को कैरोसीन मुक्त प्रदेश घोषित किया गया अर्थात राशन कार्ड पर मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया ऐसे में BPL कार्डधारियों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की घोषणा हुई जिससे पूरी जनता इसके लिए भागदौड करने लगी | इस भगदड़ में समुदाय में जरूरत मंद लोगों तक या तो सुचना नहीं पहुच रही थी | कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहाँ तक पहुचने में असमर्थ थे | जिसके तहत हमने लोगों को जागरूक किया और जरूरतमंद लोगों आवेदन भरवाए |

जागरूकता अभियान का निष्कर्ष

हमने राशन व्यवस्था को लेकर लोगों को उनकर हक़ और अधिकार को लेकर जागरूक किया जिसके लिए पोस्टर और पर्चों का इत्माल किया | जिसका मकसद था लोग स्वयं आवाज उठायें | ऐसा ही किया जहांगीरपुरी के ग्राहकों ने राशन दुकानदार ने पूरा राशन नहीं दिया जिस पर लोगों ने तुरंत शिकायत की मामला पुलिस के पास पहुँच गया अंतः दुकानदार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी और लोगों को पूरा राशन भी मिला |

अनुभव बांटना

मंच ने काम के दौरान जो सीखा और अनुभव किया उसे लोगों टक पहुंचाने की भी कोशिश की |

राशन वितरण प्रणाली को लेकर ट्रेनिंग

- जहांगीरपुरी RWA को राशन व्यवस्था को लेकर प्रशिक्षण दिया |
- रघुवीर नगर में लोगों को **case transfer** और राशन व्यवस्था / राशन कार्ड के बारे में जानकारी दी |
- आस्था NGO के स्टाफ को राशन व्यवस्था की जानकारी को लेकर ट्रेनिंग दी |
- आस्था NGO के गोविन्दपुरी और लाल कुआँ समुदायों में **case transfer** और अन्न श्री में फर्क को लेकर जानकारी दी | लोग अपना पूरा राशन कैसे ले सकते है इसकी शिकायत कहाँ और कैसे कर सकते है इसकी जानकारी दी | जिसके फ्लोउप के तहत लोगों RTI का इस्तमाल किया और MLA का घिराव कर अपना राशन पूरा लेना शुरू किया |
- एक्शन इंडिया NGO के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया |
- एक्शन इंडिया NGO के हर्ष विहार क्षेत्र में राशन को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया | जहाँ महिलाओं ने इसे जमीन पर कैसे प्रयोग करते है इसके लिए सहायता मांगी जिसके तहत दुकानदार के साथ झगड़ा हुआ और पुलिस केस भी हुआ | जिसमें एक्शन इंडिया के लोग वापस चले गए लेकिन हमारे

दो साथी रात 10 बजे तक हर्ष विहार थाने में पुलिस से जूझते रहे | पुलिस को लेकर HRLN के साथ मिलकर अभी भी यह केस चल रहा है |

- होलम्बी कलां के समूह को राशन को लेकर प्रशिक्षण दिया |
- वजीरपुर के यूथ को ट्रेंनिंग दी |

<u>नेटवर्क के तहत कार्यक्रम व अभियानों में काम के अनुभव को शेयर करना</u>

- ऑक्सफेम द्वारा आयोजित कार्यक्रम " **खाना खजाना** " में भी **case transfer** के अनुभवों को रखा |
- रोजी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली के साथ लगातार हमारी भागीदार रहे है जिसके तहत कई मीटिंगों में जुड़े और **case transfer** के बारे में बताया | इसी के तहत मुख्य मंत्री को मांग पात्र भी सौपा गया | इसी के तहत राशन व्यवस्था से लोगों बातें जानने के लिए **सर्वे** किया जिसमे हमने भी सर्वे किया |

<u>पानी और साफ़ सफाई</u>

भलस्वा की भूगोलिक व यथार्थ स्थिति को देखते हुए ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से भलस्वा में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर जहाँ इसका असर दिखाई देता है वही उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी इसका असर दिखाई देता है |
कहने को दिल्ली गरीब मूक एक विश्वस्तरीय शहर है जहाँ किसी भी सस्य का कोई स्थान नहीं है ऐसे में भलस्वा की चर्चा अपवाद लगती है | ;यकीन सच्चाई यही है की भलस्वा में इन दोनों समस्याओं की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है इस वर्ष मंच द्वरा इन्ही दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम किया गया है |

<u>पीने का पानी</u>

भलस्वा में पीने के पानी कई स्रोत है |

1. लोग अपने काम की ही जगह से भर कर लाते है |
2. DJB द्वारा जो भी पिप लाइन से पानी आता है उसका इस्तमाल होता है |
3. टेंकर द्वरा पानी (अच्छा / खराब) जिसे कई दिनों तक इस्तमाल किया जाता है |
4. कुछ लोग खरीद कर भी पीते है |
5. अपवाद जैसा है गिने चुने लोगों के घरों में फिल्टर करने की मशीन लगी है |
6. अधिकांश लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है वे भू-जल (हेंडपंप) ही इत्माल करते है |

<u>जन शिकायत आयोग (PGC) में भलस्वा के पानी की समस्या</u>

<u>जैसाकि पिछले वर्ष से PGC में hearing शुरू हो चुकी थी उसी कड़ी में आगे</u>.....

- PGC ने सख्त निर्देश दिये की पानी से कालरा जैसी जानलेवा बिमारी होती है इसलिए भलस्वा में पानी की स्थाई व्यवस्था की जाय और उसके लिए विभाग अपना प्लान लेकर आये |

- PGC से ज्वाइंट इन्पेक्सन का निर्देश लेकर आये जिसके निर्देशानुसार भलस्वा में जब तक स्थाई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अस्थाई व्यवस्था की जाय | इसके लिए अधिकारिओं के साथ समुदाय में विजिट किया और सर्व प्रथम 47 पॉइंट तय किये जहाँ पर टैंकर रुक सकेंगे |
- टैंकर लगातार हो इसके लिए लोगों को जागरूक किया जिसके लिए नुक्कड़ मीटिंग की गयी |
- 3 बड़ी पब्लिक मीटिंग की जिसमे 150 से 200 लोगों की संख्या रही |
- शिकायत कैंप लगाये जिसमे १३२ लोगों ने व्यक्तिगत शिकायतें लिखवाई जिसे लेकर 25 महिलायें DJB के CEO को मिलने गई | महिलाओं के समूह को देखकर उन्हें वही रोक दिया गया और पुलिस को बुला लिया गया |अंतः CEO से मीटिंग हुई जिसमे जल्दी ही काम करने का आश्वासन मिला |
- इस शिकायत की कॉपी PGC को भी भेजा |
- टैंकर के नहीं आने पर शिकायत कहाँ करे और कैसे करें लिखित या कंट्रोल रूम में फोन से आदि से शिकायतें कैसे करें | इसके बारे में सीखाया गया |
- PGC में ही दिल्ली जल बोर्ड की पोल खुली | लोग जब भी शिकायत करते तो DJB कहना होता था की गड़बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उनके टैंकर में GPS लगा होता है | लोगों की शिकायतें लगातार बड रही थी और यही शिकायतें PGC में जारही तो DJB को मानना पड़ा की GPS अभी प्रक्रिया के तहत चल रहा है और DJB ने यह बाताया की उनके कंट्रोल रूम में भी 38 लोगों की शिकायतें रिकार्ड हुई है |
- टैंकर सुपरवाईजर के साथ लोगों की दो मीटिंगे करवाई जिससे टैंकर की गड़बड़ी ना हो |
- लोगों तक जानकारी पहुंची | निष्कर्ष यह की इस समय टैंकर की समस्या को लोग स्वयं ही हल कर लेते है |

- **<u>PGC के चेयरमेन के बदलाव से निर्देश भी बदल गए</u>**

यह भलस्वा का दुर्भाग्य कह सकते की अधिकारी बदल गया और नये चेयरमेन ने पिछले निर्देश गतल बताया कहा की उन्हें DJB की स्थिति नहीं पता थी भलस्वा को पानी नहीं मिल सकता क्यूंकि द्वारिका जैसी DDA द्वारा बसाई गई कालोनी को तक DJB पानी नहीं दे सकता और बिना किसी निर्णय के इस केस को बंद कर दिया गया |

- **<u>जबाबी कार्यवाही</u>**

PGC के व्यवहार खिलाफ पत्राचार शुरू किया गया भलस्वा को सरकार ने बसाया है है तो पानी देना भी उसी की जिम्मेदारी है | द्वारिका भले ही DDA का हो लेकिन वहाँ वही लोग जा रहे जो पानी खरीद कर इस्तमाल कर सकते है | तो भलस्वा की तुलना उससे कैसे हो सकती है |

- **<u>DRTI एक्ट 2001 (दिल्ली सूचना का अधिकार) का इस्तमाल</u>**

DRTI एक्ट से 30 दिन में जबाब मिलता है वरना इसकी शिकायत PGC को ही जाती है जहाँ पर इसका जबाब विभाग को देना ही होता है |

भले ही एक रास्ता बंद हो हमने दुसरे तरीके से काम शुरू किया | DJB को दी गई हमारी अनगिनत शिकायती पत्र पर DRTI का प्रयोग किया मुख्य सवाल के रूप यही सवाल था मंच द्वारा लिखे गए पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई | जिसके जबाब के लिए फिर से PGC आना ही होगा |

- **<u>भलस्वा के टैंकरों पर राजनीति</u>**

मंच और लोगों की मेहनत से भलस्वा में आ रहे 47 टैंकरों पर नेताओं और प्रधानों ने अपनी बोट की राजनीति शुरू कर दी और लोगों को कहा टैंकरों की व्यवस्था उनके प्रयासों से हुई है | महिलाओं उन्हें रोका और कहा लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो यह सब हमारी मेहनत से हुआ है | हमारी फाइलें इसका सबूत है | यह महिलाओं के काम करने का हौसला बोल रहा था |

- **<u>भू-जल सेम्पल और भू-जल रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री से मिलना</u>**

मुख्यमंत्री सेम्पल देखकर चौक गई बोली ओह ..... ऐसा पानी भलस्वा का ? CM ने लेटर पर दिल्ली जल बोर्ड को लिखा भलस्वा के लिए टैंकर की व्यवस्था की जाय |

- **<u>CM का लेटर और दिल्ली जल बोर्ड</u>**

DJB ने CM के इस प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं किया अटकलें लगाईं | कहा हम इससे ज्यादा नहीं कर पायेंगे | हमारा संघर्ष जारी है फिरहाल 47 टैंकर लगातार आ रहे है |

<u>साफ़ सफाई</u>

जब से भलस्वा बसा है तब लगातार सफाई कर्मचारी लोगो की झडप होती रही है कभी नाली की सफाई तो कभी कूड़े के ढेर को लेकर | लेकिन महत्वपूर्ण यह था की भलस्वा में गन्दी सबसे बड़ा कारण यह था की जब से भलस्वा बसा है तब से गंदे पानी की निकासी ही नहीं हुई जिसकी वजह गन्दा पानी समुदाय के आस पास ही जमा है जिसकी वजह से गन्दी का कोई हल ही नहीं दिखाई दे रहा था | यह एक नीतिगत मसला था जिसे छोटे अधिकारियों द्वारा हल नहीं किया जा सकता था | अगर पानी का आउटफाल हो जाय तो समस्या का हल निकल सकता है और यह भी की MCD और DUSIB भी एक दुसरे के उपर दोष रोपड़ कर रहे थे यह काम उनके अंतर्गत नहीं आता है ऐसे में भी इस मसले को PGC के अलावा कोई हल नहीं कर सकता था |
जिस तरह पानी के मुद्दे पर कुछ रास्ता PGC से दिखाई दिया उसी की तर्ज में इस मुद्दे को भी PGC ले गए |

<u>PGC में साफ़ सफाई का मुद्दा</u>

1. PGC जाने से MCD के दफ्तर में नोटिस पहुँच गया और **hearing** से पहले MCD के 4 अधिकारियो की टीम हमारे सेंटर पहुँच गई कुछ दिक्कत हो तो हम हल करेंगे वहन जाने की क्या जरूरत है आदि माहौल

साफ़ सुथरा चूना डाला हुआ आदि | लेकिन यह थोड़े समय का भय था फिर से वही स्थिति हो ही जानी थी | अधिकारियों ने अपनी समस्या को सामने रखा पूरा जमा हुआ पानी तो वे नहीं साफ़ कर सकते |

2. हमें पता था इसी लिए हम PGC में गए है जहाँ पर जिम्मेदार अधिकारीयों को बुलाया जा सके और जिम्मेदारी सौपी जा सके |
3. PGC में कई **hearing** हुई हर बार कुछ न कुछ सफाई अधिकारियों की ओर से आ ही जाती एक बार तो अधिकारीयों ने स्वयं को बचाने के लिए भलस्वा के RWA और प्रधान से अपने काम के बारे में प्रशसनीय पत्र लिखवा लिया | PGC मेम्बर ने कहा काम हो तो रहा है | हमने केवल नये फोटोग्राफ सामने रख दिए अधिकारियों को डांट पड़ी |
4. **<u>समुदाय में प्रचार, नुक्कड़ मीटिंग और 3 पब्लिक मीटिंग</u>**

गली गली नुक्कड़ मीटिंग की 3 पब्लिक मीटिंग की जिसमे सौ सवा सौ लोग एकत्र हुए जिसमें PGC में अधिकारियों और समुदाय के प्रधान व RWA के रवैये को लेकर बात हुई महिलाओं को नाराजगी थी | महिलाओं ने इन सबका उनके घर जाकर घिराव किया और स्पष्ट बोला की यह समुदाय हमारा है आप इसके ठेकेदार नहीं बन सकते |

109 शिकायतें भी लिखी गई | जिसे लेकर महिलाओं का पूरा समूह DC के दफ्तर पहुँच गया और DC से बात की इस बार भी अधिकारियों को डांट पड़ी | यही शिकायतें PGC को भेजी गई |

5. **<u>महिलाओं के साथ सेनीटेशन इंस्पेक्टर की मीटिंग</u>**

महिलाओं के मीटिंग में इंस्पेक्टर का फोन नम्बर माँगा जिससे समुदाय की सफाई ठीक से हो सके | अब महिलायें जहां गंदगी देखती है फोन बात का र सफाई करवा लेती लेकिन पानी निकासी का मसला अभी भी पगक में ही है |

6. **<u>PGC का निर्देश रुका हुआ पानी पम्प से निकला जाय</u>**

PGC के निर्देश के अनुसार यह काम DUSIB को सौपा गया लेकिन DUSIB ने अनदेखा कर दिया | निर्देश की कॉपी लेकर 50 महिलाओं का ग्रुप DUSIB के दफ्तर पंहुचा पम्प को चलाया जाय | महिलाओं के दबाव का असर ही था कि कुछ दिन तक पम्प चला लेकिन अधिकारीयों तेल नहीं का बहाना बना कर उसे बन कर दिया गया | अगली **hearing** में PGC ने सख्त निर्देश दिए | MCD, DUSIB, DEMS इन तीनों विभागों के उपर दबाव बना |

7. **<u>भलस्वा में D-1 ब्लाक में स्थित शुलभ शौचालय ध्वस्त होना और जीर्नोधार</u>**

इस शौंचालय का टैंक टूट कर गिर गया गंदगी खुली हुई थी 12.5 वर्गमीटर के घर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ बदबू न हो महिलाओं ने अपने स्तर पर (MLA) कोशिश की लेकिन किसी समस्या का हल नहीं किया | महिलाओं ने मंच से हस्तक्षेप करने को कहा | मंच सबसे पहले फोटोग्राफी की उच्च अधिकारी चीफ इंजीनियर को लिखा | 3 महीने की लम्बी प्रक्रिया के बाद शौचालय को दोबारा से चालु कर दिया गया |

1. **<u>पानी और साफ़-सफाई के मुद्दे पर जनसुनवाई</u>**

पानी और साफ़ सफाई का सीधा रिश्ता इंसान के स्वास्थ्य से है जब से लोगों का पुनर्वास हुआ है तब से लगातार लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण गन्दा पानी जिसके इस्तमाल करने से हुआ है विभाग के

दरवाजे खटखटाते 13 वर्ष बीत जाने पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है इस लिय अब मंच की भूमिका की लोगों और अधिकारियो को एक मंच पर लाया जाय जिससे बात आमने सामने हो सके |

- 56 लोगों की केस स्टडी तैयार की |
- 914 परिवारों से पानी और सफाई की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की |
- 6 अधिकारी (MCD, DJB, DUSIB) और DJB यूनियन अधिकारी शामिल हुए |
- 2 समाजिक कार्यकर्ता (CURE और सैंट स्टीफेंस) शामिल हुए |
- निगम पार्षद भी शामिल हुए |
- 200 से 300 लोगों समुदाय से शमिल हुए जिन्होंने जैम कर अपनी शिकायतें की और पीने के पानी और साफ़ सफाई की स्थाई व्यवस्था का मांग की |

<u>निष्कर्ष</u>

1. नेता और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आये सभी नीतिगत मजबूरी जताई |
2. पानी की समस्या पर पानी के टैंकर बढाने का आश्वासन दिया |
3. सुलभ शौचालयों की स्थिति पर DUSIB ने कहा यह ठीक करवाएगा |

आगामी अधिअक्रियों की इस बात को जमीन पर उतारने के लिए हमें इसका फ्लोउप करना पड़ेगा |

<u>शिक्षा</u>

इस समय अधिकांश बच्चे स्कूल में प्रवेश तो कर गए है लेकिन स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने की वजह से स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है | इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ काम कर पाए |

1. **<u>स्कूल का निर्माण</u> -** पिछले 2 वर्षों से चल रही प्रक्रिया के तहत एक स्कूल का निर्माण शुरू हुआ है |

2. **<u>डेस्क की व्यवस्था</u> -** प्राइमरी स्कूलों में बच्चो के बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था हो पाई |

3. **<u>स्कूलों में बच्चो का दाखिला</u>** - महिलाएं ने 4 ऐसे बच्चो का स्कूल में दाखिल करवाया जो गाँव से शहर आये थे और जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे | उनका साधारण एफिडेविट से दाखला करवाया |

4. **<u>दो पब्लिक मीटिंग</u>** - स्कूलों की समस्या को लेकर 2 पब्लिक मीटिग की जिसमे लगभग 300 लोग एकत्र हुए | जिसमे स्कूलों की समस्याए निकल कर आई |

5. **<u>शिकायत कैंप से सफलता तक</u>** - पब्लिक मीटिंग के बाद 4 शिकायत कैंप लगाये गए जिसमे समुदाय के बच्चो ने ने सहयोग किया 212 शिकायतें लिखी गई | इन शिकायतों के फ़ाइल् करने के बाद स्क्कोल में चौकीदार की व्यवस्था हुई | शिक्षक कक्षाओं में दिखाई देने लगे | पीने के पानी के 2 से 3 दिन में पानी का टैंकर आने लगा |

6. **<u>मध्यान भोजन पर महिलाओं की निगरानी</u>** - 16 जुलाई 2013 को बिहार में घटी घटना के बाद महिलाओं ने स्कूल के खाने की निगरानी शुरू की | जिसकी निगरानी के लिए खाना बनाने वाली संस्थाओं का भी विजिट किया |

7. **<u>भलस्वा में स्कूल के निर्माण के लिए प्रक्रिया -</u>**

- पत्राचार चल रहा है |
- शिक्षा विभाग के साथ स्कूल लेंड को मीटिंग और जमीन के लिए DUSIB को पत्र लिखवाना |

<u>आवास</u>

मौजूदा सरकार के अनुसार 2015 तक दिल्ली को स्लम फ्री का दिया जाएगा अर्थात विस्थापन का कहर टूटेगा | भलस्वा ने विस्थापन का दर्द सहा है इसलिय पुनर्वास की तकलीफें क्या होती है उसके लिए क्या कर सकते है | इस उदेश्य से मंच में जहांगीरपुरी में स्लम बस्तियों के लोगों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना शुरू किया |

<u>जहांगीरपुरी में RWA के साथ मीटिंग</u> - RWA कई ब्लाक में काम करता है | क्योकि अधिक लोगों तक जानकारी पहुचे इस मकसद से लोगों को आने वाले खतरे से आगाह किया | पालिसी की जानकारी दि गई, लोगों ने इसे समझा और जानकारी लोग तक पहुचाने में मदद करने की बात की |

<u>4 ब्लॉक में जागरूकता कार्यक्रम</u> - बहुत ही नाजुक मुद्दा है इसे ध्यान रखते हुए हम लोहों के बीच गए | लोगों के घर घर , गली गली में नुक्कड़ मीटिंग की | पब्लिक मीटिंग की | जिस दौरान इन बस्तियों के दबंग और प्रधानो के साथ झड़पें भी हुई इसके बावजूद हम लोगों के बीच अपनी बात रखने में सफल हो पाए |

<u>3 बड़ी पब्लिक मीटिंग</u> - पब्लिक मीटिंग में लोग अपने को नहीं रोक पाए और अपनी बात की वे इस जगह से नहीं जाना चाहते | उनकी यादें यहाँ से जुडी है बच्चो के स्कूल है और रोजगार भी है | इसलिए वे यहाँ से नहीं जाना चाहते | लोग इस बात पर सहमत हो गए उन्हें अपना दस्तावेजीकरण (सर्वे) करना चाहिए जिससे वे उसका इस्तमाल कर सकें या सरकार के आंकड़ो को चुनौती दे सके |

समुदाय में स्वयं का सर्वे - लोगो ने स्वयं कासर्वे शुरू कर दिया है |

<u>आवासीय मुद्दे पर कार्यशाला</u> - यह कार्यशाला जहांगीर पुरी व भलस्वा के लोगों के लिए आयोजित किया गया था जिसमे 45 लोग जुड़े | झुग्गी झोपडी और पुनर्वास कॉलोनी की सरकारी अधिकारियों की दृष्टी में क्या अहमियत है और JNNURM का मकसद पर चर्चा हुई जो की किस तरह से झोपडी बस्तियों के लिए घातक है | लोगों ने स्वयं की जानकारी ली की वे अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगें |

<u>लैंड सर्वे</u> - यह सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है जिसे भलस्वा में 914 परिवारों के साथ किया गया है | जिसमे लोगों के शहर में आने का इतिहास और आवास पर हुए खर्चे का लेखा जोखा निकला है | लोगों की जिन्दगी में पुनर्वास

से क्या फर्क आया यह भी दर्शाता है | यह सर्वे भलस्वा के लाइसेंस के मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है | जिससे अगर भलस्वा में सरकार की और से कोई भी प्रतिक्रिया का जबाब दिया जा सकता है |

<u>सर्वे को लेकर समुदाय में जागरूकता</u> - यह महत्वपूर्ण सर्वे को लेकर हम लोगों के बीच जाकर फैलाने की कोशिश कर रहे है |

<u>Out station visit –</u>

यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमे सीखने और सीखाने का मौका मिलता है | जिससे हमारे काम मेंजुनये आडियाज जुड़े | जो सबसे ज्यादा कर्णछपरा में इस्तमाल हुआ |

<u>उदयपुर का दौरा</u>

इसका आयोजन MKSS किया | यह कार्यक्रम युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी से जुडा था | यहाँ पर सीखने के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले लोगों से मुलाक़ात हुई जिसमे सबसे अहम मुद्दा था सोशल ओडिट | इसे जमीन में कैसे किया जाय इसके लिए हैदराबाद जाना था |

<u>हैदराबाद</u>

युवओं की एक टीम अपने खर्चे से हैदराबाद के गाँवों जाकर इसका प्रयोग सीख कर आये |

<u>कर्ण छपरा</u>

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है कर्णछपरा यहाँ काम हमारे युवा वालंटियर के द्वारा ही और यही हैदराबाद के अनुभवों से काम किया गया | (जिसकी रिपोर्ट अलग से भेज रहे है)

<u>म. प्र. में कोतमा का विजिट</u> -

यहाँ पर हम अपने राशन और RTI के अनुभव बाटने गए गए थे साथ ही कोयले की खदानों की त्ल्लीफों को समझ कर आये यह एक महत्वपूर्ण विजिट था सीखने के बाद लोगो ने बहुत से कार्य स्वयं किये |

<u>दस्तावेजीकरण</u>

हमने अपने RTI के अनुभवों को पुस्तिका के रूप में निकला है जिससे यह लोगो तक आसानी से पहुँच सकें |

<u>कार्यक्रम</u>

8 मार्च 2013

300 महिलाओं के साथ मनाया गया यह दिवस का मकसद था महिलाओं का संघर्ष अन्य महिलाओं तक पहुँच सके जिससे महिलाए आगे बढे |

<u>दिवाली सेलिब्रेशन</u>

200 महिलाओं के साथ त्यौहार सेलीब्रेशन के साथ समुदाय में पीने के पानी और साफ़ सफाई पर चर्चा भी रही जिसमे ही जनसुनवाई की योजना पर जोर दिया गया |

समुदाय में त्यौहार और बस्ती दिक्कत

यह त्यौहारों को देखते हुए एक सेलीब्रेशन था जिसमे 200 महिलायें एकत्र हुई | महिलाओं ने बच्चों की शिक्षा पर चिंता व्यक्त की और आगे की रणनीति तय की |

कार्यशालायें -

सुचना का अधिकार के तहत फाइल निरिक्षण -हमने RTI को फाइल निरिक्षण को बेहतर तरीके से सिखने के लिए इस कार्य शाळा का आयोजन किया |

REPORT और चिट्ठी लिखना- रिपोर्ट लिखना और चिट्ठी लिखना भी एक कला है हमने इन चीजों को और बेहतर तरीके से लिखने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया |

आवास और जमीन - इस कार्यशाला का आयोजन बस्ती के लीडर स्तर के लोगो के लिए किया गया ताकि लोग अपनी बस्ती व सरकारी नीतियों के बारे में जान सके | इसमें खतरा केंद्र के साथियों ने हमारी मदद की |

परिचर्चा

हिन्दू कॉलेज , दिल्ली विश्व विद्यालय में RTI पर परिचर्चा - हिन्दू कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप ने RTI पर एक परिचर्चा का आयोजन किया जिसमे 30-40 छात्र शामिल हुए जिसमे RTI के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ बस्तियों के अनुभवों को भी साझा किया |

प्रशिक्षण -

शक्करपुर में युवाओं को RTI प्रशिक्षण - यह एक युवाओं का समूह है इनकी जरूरत के अनुसार हमने इन्हें rti की प्रशिक्षण दिया जिसका युवा अपने काम में इस्तमाल कर पा रहे है |

होलम्बी कलां के युवा समूह को प्रशिक्षण - इस समूह के साथ पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे थे जिनके साथ हमने साफ़ सफाई और राशन के मुद्दों पर काम किया था अब यह युवा अपना काम स्वयं करने में सक्षम दिखाई दिए हमने इन्हें काम की फाइलें सौपी दी जिससे वे काम को आगे बाढा सकें |
इस समय युवाओं को काम को लोगों के बीच में कैसे लेके जाय की समझ बनानी थी जिस पर हमने युवाओं को प्रशिक्षण दिया |

दिल्ली विश्वविद्यालय (हिन्दू कॉलेज) में RTI पर परिचर्चा - हिन्दू कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप के साथ यह परिचर्चा रही जिसने 30 से 40 student शामिल थे | rti के तकनीकी पहलुओं के साथ आम लोगों में RTI का इस्तमाल पर चर्चा हुई जिसमे भलस्वा के लोगों का RTI संघर्ष का अनुभव भी शेयर किया गया |

आस्था के साथ PDS का ट्रेनिंग - आस्था के साथ यह हमारा दूसरा ट्रेनिंग कार्यक्रम था जब हमने उन्हें राशन व्यवस्था के बारे में सीखाया |

अन्य

भलस्वा में पुलिस सर्वे का विरोध - पुलिस लोगों को राशन कार्ड सर्वे के नाम पर गुमराह कर यह सर्वे कर रही थी जिसमे घर के छोटे बच्चे से लेकर हर सदस्य का लेखा जोखा माँगा जा रहा | जिसकी सुचना हम तक पहुंची | यह चौकाने वाली बात थी क्योंकि पुलिस का राशन के साथ कोई लिंक नहीं होता हमने राशन दफ्तर यह जानकारी मांगी तो यह निराधार थी हने लोगों को इससे आगाह किया | राशन का कोई सर्वे पुलिस नहीं कर ही सकती | लोगों ने पुलिस से आदेश की कॉपी मांगी | पुलिस के पास कोई भी आदेश नहीं था फिर यह किस लिए | लोगों पुलिस के डराने के बावजूद 3 दिन तक इसका कडा विरोध किया और सर्वे का रोका पाने में सफल हुए |
ऐसा भी यह भी देखा गया है गुनाह किसी का और सजा किसी को मिलती है दिल्ली में जो भी अपराधिक घटनाएं होती है जिसका जबाब पुलिस को देना ही होता है |ऐसे में गुनाहगार पकड़ा गया कहना आसन नहीं होता है | यह अपराधिक सर्वे था |

नेटवर्क कार्यक्रम

25 से ज्यादा नेटवर्क कार्यक्रम में जुड़े |

1. **साझा मंच** - यह दिल्ली के 70 सन्गठन का मंच है जिसने शहरीय गरीब के सभी मुड़े उठाये जाते है जिसके तहत बस्तियों में विजिट , एक्सपोजर , कार्यशालाओं और समाजिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलता है | जिससे सामूहिक ताकत का एहसास होता है |
2. **अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच** - हम 2009 -10 से ही इसके साथ जुड़े है जिसमे समान शिक्षा की बात करते हुए K.G. से P.G. तक निःशुल्क शिक्षा के लिए संघर्ष जारी है | मंच के साथ मिलकर इसी सम्बन्ध में 21/10/2013 को सरकार को मांग पत्र सौपा गया |
3. **महिला हिंसा को लेकर CSR (सेंटर फॉर सोशल रिसर्च**)- समुदाय में काम के दौरान ही कुछ महिला हिंसा को लेकर भी केस सामने आते है हमने ऐसे 8 केस CSR को सौपे जिसको हम मोनिटर कर रहे है | इन महिलाओ के साथ एक मीटिंग व काउसिलिंग हो चुकी है |
4. **चाइल्ड लाइन बलिया -** कर्णछपरा में काम के दौरान हमें एक बच्चा मिला जो शारीरिक विकृति से जूझ रहा था जिसका आपरेशन माँ-बाप की हैसियत से बाहर थी जिसके लिए हमने कई NGO व हेल्थ संस्थानों को लिखा और निवेदन किया | अंतः यह केस बलिया चाइल्ड लाइन ने अपना लिया | जिसने आश्वासन दिया जल्दी ही डॉक्टरों की टीम देखेगी काफी लम्बे समय के बाद बच्चा अब आम बच्चो की तरह जिन्दगी जी रहा है |
5. **साबदा घेबरा के लोगों का भलस्वा में एक्सपोजर विजिट -** साबदा श्रम शक्ति संगठन से 20 लोगों की एक टीम भलस्वा के अनुभवों व संघर्ष जानने व सीखने के लिए आई जिससे विचरों और संघर्षों का आदान प्रदान हुआ और भविष्य में मिलकर काम करने की बात हुई |

रिपोर्ट वर्ष 2014 मार्च - 2015 जुलाई (भाग -5)

राशन

भोजन का अधिकार की बात करते ही राशन का मुद्दे की बात करना स्वभाविक है मंच ने काम की शुरुवात ही राशन के मुद्दे से की क्योंकि समुदाय में यह अहम मुद्दा है हर व्यक्ति हर घर में राशन व्यवस्था को लेकर बहुत शिकायत रहती है इस व्यवस्था में विभागीय तौर पर भी बहुत सारी कमियां है जिसके लिए मंच लगातार लोगों के साथ काम कर रहा है |

खाद्य सुरक्षा बिल

cash transfer के बाद अन्नश्री योजना को लाया गया जो केवल चुनावी एजेंडा बन कर ही रह गई जिसे चुनाव के बाद बंद कर दिया गया इसी समय खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया है जिसके तहत पिछले दो वर्षों से आवेदन की ही प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है जिसमे काफी खामिया है जिसके लिए विभाग के साथ पत्राचार और मीटिंग की है जिसके तहत निम्न कार्य हुए |

1. खाद्य सुरक्षा के तहत बन रहे राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में लिया गया था जिसकी वजह अधिकांश लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो रहे थे क्योंकि लोगों के पास आधार कार्ड ही नहीं थे जिसके लिए कमिश्नर के साथ बैठकें और पत्राचार किया गया तत्पश्चात कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमे यह बात कही गई लोग आधार की जगह पर जनसंख्या पंजीकरण नम्बर भी लगा सकते है यह लोगों के लिए राहत भरा था |
2. कार्ड सत्यापन में धांधली चल रही थी | सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सत्यापनकर्ता को लोगों के घर घर जाकर ही सत्यापन करना था लेकिन लोगों को घरों से दूर बुलाकर उनका समय नष्ट किया जा रहा था साथ ही सत्यापन के पैसे भी लिए जा रहे थे | इसका भंडाफोड़ किया गया जिसके लिए जान का खतरा भी उठाना पडा जिसके खिलाफ विभाग और पुलिस को शिकायत की गई और प्रक्रिया को सुचारू किया गया |

3. कितने कार्ड बने कितने नहीं इसके लिए सर्कल के अधिकारी (FSO) और सह आयुक्त (AC) से मीटिंग करना चिठ्ठियाँ लिखी गई | कुछ लोगों के कार्ड बनकर आ भी रहे है तो उसमे पता गलत है या फिर परिवार के सभी सदस्यों के नाम नहीं चढाये गए है इस आकड़े ठीक से कैसे निकला जाय इसके लिए हमने भलस्वा और जहाँगीरपुरी में 1254 परिवारों का सर्वे किया |
4. सर्वे का आकड़ा चौकाने वाला था 70 फीसदी लोगो के कार्ड ही नहीं बने थे और 30 फीसदी लोगों उपरोक्त गलतियाँ थी यह आकड़ा तीन सर्कलों (2, 4, 5) का था | इसके आधार पर विभाग को शिकायते की और बैठकें की हालाकि विभाग ने सच्चाई को मानने से इंकार कर दिया जबाब था लोगों की कोई शिकायत नहीं आयी है इसलिए हमारी शिकायत निराधार है |
5. यही बिडम्बना है की लोग लिखना पढना ही नहीं जानते तो शिकायत कहाँ से होगी जिसका फायदा अधिकारी उठाते है इसके फलस्वरूप हमारे लिए यह बेहतर हथियार रहा क्योंकि दिल्ली के 70 सर्कल में से सर्कल 5 (जिसका सम्बन्ध सीधे हमारे क्षेत्र से था) में सबसे ज्यादा संख्या और अनुपात में लगभग 80 फीसदी कार्ड बन पाए |
6. इस बार लोगों के कार्ड डाक (post) भेजे जा रहे जिसमे डाकिया ने काफी गड़बड़ की जिसकी शिकायतें लोगों ने की डाकिया कार्ड देने के पैसे मांग रहा है वरना कार्ड नहीं दे रहा | हमने डाकिये के साथ भी मीटिंग की और उसे समझाया लेकिन डाकिये ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी जिसके खिलाफ शिकायत डाक विभाग को की काफी फोलोउप के बाद डाकिये को नौकरी से हाथ धोने पड़े |
7. जिन लोगों के कार्ड बन कर नहीं आये थे 649 लोगों की शिकायतें, शिकायत कैम्प लगा कर और और लोगों के पास जाकर शिकायतें लिखी गयी | जिस पर अधिकारीयों ने आनाकानी की लोगों फिर से दफ्तर भेजने की बात पर जोर दिया जा रहा था लेकिन मसले को आगे लेकर जाने से विभाग को काम करना पड़ा और लोगों के कार्ड बन कर आने लगे अभी भी प्रक्रिया जारी है विभाग सभी की विस्तृत जानकारी लिखकर भेज रहा है |

पानी और साफ़ सफाई

पानी और साफ़ सफाई दोनों ही मुद्दे एक दुसरे के साथ जुड़े है और दोनों ही मुद्दों का सीधा सम्बन्ध लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुडा है | जीने रहने के अधिकार की बात करे तो प्राथमिक जनसुविधा के अंतर्गत पानी और साफ़ सफाई प्रथम श्रेणी में आती है इंसान कुछ समय के लिए बिना खाना खाये जी सकता है लेकिन पानी और साफ़ सफाई के बिना नहीं जी सकता है इसके लिए भलस्वा के लोग लगातार संघर्ष कर रहे है |

पीने का पानी

भलस्वा में पानी का मुद्दा नीतिगत मसला बन गया है विभागों का गैर जिम्मेदारी भरा रवैया एक दुसरे के प्रति टालामटोली का रहा है जिसके बीच लोगों की जिन्दगियां जूझ रही है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं होने की वजह से लोगों को भूजल इस्तमाल करना पड़ा जिसे विभाग ने अनदेखा किया विभाग ने यह कह कर अपना पल्ला झाड लिया कि पुनर्वास कॉलोनी में पानी के कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है इसको लेकर हम PGC (जन शिकायत आयोग) में गए एक लम्बे संघर्ष के बाद जहाँ से लोगों कुछ राहत मिली है |

1. जब तक कोई स्थाई व्यवस्था नहीं होती तब तक भलस्वा में टैंकर से पानी सप्लाई किया जाएगा इसके तहत अधिकारियों के साथ भलस्वा का विजिट किया और टैंकर के 150 पॉइंट (कहाँ कहाँ) सुनिश्चित किये गए जिसकी जिम्मेदारी समुदाय के लोगों को सौपी गई इस समय दिन में 18 से 22 टैंकर रोज आ रहे है जिससे से लोगों को पीने का पानी मिल पा रहा है |
2. लोग जागरूक हुए टैंकर को मोनिटर करते है और टैंकर की समस्या को लोग स्वयं ही निपटा लेते है | नहीं आने समस्या को लेकर दफ्तर भी चले जाते है |
3. पानी का भूमिगत टैंक (UGR) के लिए जगह सुनिश्चित कर DJB को आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है हालाकि आदेश के बाद भी आदेश लागू करवाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी |
4. दिल्ली जल बोर्ड ने एक और योजना को **water ATM** रूप में लोगों के सामने रखा जिसे लोगो के उपर थोपा जा रहा था इसके लिए हमने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया और उन क्षेत्रों का विजिट जहां इसे लगाया गया था लोगों के उस अनुभव को भलस्वा में बांटा जिसके तहत पर्चे और पोस्टर लगा कर लोगों को जागरूक किया जिससे लोगों ने स्वयं ही निर्णय लेकर इस योजना को नकार दिया नकार दिया और इस प्राइवेट कंपनी को सर्वे नहीं करने दिया |
5. महत्वपूर्ण सफलता यह रही है की लोगों का संघर्ष दो विभागों के बीच झूल रहा था दोनों ही विभाग इस समस्या को एक दुसरे पर थोप रहे थे इस समय मंच के प्रयासों से यह समस्या एकल खिड़की पर आ गई है अर्थात DUSIB ने इसे दिल्ली जल बोर्ड को हेंडओवर कर दिया है DUSB को डेफिसेन्सी चार्ज देना है जिससे DJB समुदाय में एक नई व्यवस्था करेगी |
6. इस समय समुदाय स्थाई समाधान की और विभाग का ध्यान आकर्षित कर उसकी मांग पर जोर दिया जा रहा है |

<u>साफ़ सफाई</u>

साफ़ सफाई का मतलब नाली साफ़ करना और रोड पर झाड़ू लगाने भर के विभाग के भरम को हमने तोडा है मंच ने साफ़ सफाई को एक बड़े स्तर में प्रस्तुत किया है जिसमे भलस्वा के पूरे पर्यावरण की बात को उठाया है पिछले 15 वर्षों से घर के काम के बाद निकला गन्दा पानी समुदाय के चारों एकत्र है जिसकी वजह से मक्खी मच्छर के अलावा पूरा वातावरण खराब हुआ है यही नहीं बल्कि जिसकी वजह से भूजल और दूषित भी हो रहा है जिसकी वजह से विभागों में खलबली है | इस साल हम इन बिन्दुओं कुछ राहत दिला पाये |

1. भलस्वा का टनों के हिसाब फैला कूड़ा उठाने के लिए लोडर का प्रयोग हो रहा है |
2. वर्षों से अनदेखा किये गए बड़े नालों की सफाई समय समय पर मशीनों से होने लगी है |
3. PWD जिसे भलस्वा से लेना देना नहीं था उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की, कि उनकी वजह से भलस्वा में दिक्कत आ रही है |
4. PGC में भी इस मसले को उठाया गया है जिसकी वजह से भलस्वा में PWD, DUSIB, MCD और DEMS ने मिलकर भलस्वा का विजिट किया गया है और इस समय विभागों में भलस्वा को लेकर दबाव बना हुआ है |
5. 15 साल बाद अब मंच संघर्ष से 4 ढलाव के लिए जगह सुनिश्चित हो गई है |
6. सबसे महत्वपूर्ण यह की DUSIB द्वारा साफ़ सफाई का मसला अब MCD को हैण्डओवर हो गया है जिसकी वजह से यह मुद्दा भी एकल खिड़की पर आ गया है |

शिक्षा

सन 2009 में निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 संसद में पारित हुआ इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है जिस पर सबका अधिकार होना चाहिए लेकिन दुःख की बात है आज भी भारत - विकिपीडिया के आकड़े के अनुसार भारत में 64.8 प्रतिशत ही साक्षरता है |

साक्षरता का प्रतिशत बड़े इसके लिए सर्वशिक्षा जैसे अभियान चलाये गए 2009 में RTE एक्ट पारित हुआ लेकिन अगर हम शिक्षा के स्तर की जमीनी हकीकत देखे तो यह सब कागजी दस्तावेज ही दिखाई देते है | स्कूलों की उचित व्यवस्था किये बिना सब ब्यर्थ है बच्चे स्कूलों में जानवरों की तरह भरें पड़े है जहां ना ही पूरे शिक्षक है ना ही बैठने की व्यवस्था, ना ही पीने के पानी व टॉयलेट की व्यवस्था है ऐसे में बच्चों को स्कूल भेज कर केवल साक्षरता आकड़े ही एकत्र किये जा सकते है |

भलस्वा एक पुनर्वास कॉलोनी है जहाँ पर मास्टर प्लान के मानको के आधार पर पुनर्वास से पूर्व ही स्कूल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को तैयार करना था लेकिन पुनर्वास के समय यहाँ कोई भी स्कूल नहीं था जिसकी वजह आस पास के स्कूलों में बच्चों के दाखिले की कोशिश की गई क्यूंकि स्कूलों में सीटें फूल थी जिसकी वजह से अधिकांश बच्चो का स्कूल छूट गया | लगभग 15 वर्षों बाद भी स्कूल की ठीक से कोई व्यवस्था नहीं की गई है |

भलस्वा में ही सीनियर सेकंडरी स्कूल का निर्माण के लिए शिक्षा विभाग और DUSIB से दूर दराज गाँव से रोजगार की तलाश में आये यह लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते विशेषकर यहाँ की महिलाओं की बात करें तो अधिकांश निरक्षर है निरक्षर होते हुए भी पूर्ण रूप से जागरूक है शिक्षित है अपने हक़ और अधिकार की बात जानती है यही नहीं यह सभी अपने बच्चो का उज्ज्वल भविष्य की महत्वता को समझती है इसी लिए अपने बच्चों के सुनहरे कल के लिए स्कूली व्यवस्था ठीक करने के लिए इसमें हस्तक्षेप कर स्कूली व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में काम कर रही है, महिलाए जानती है कि किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तीकरण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है | जिसके तहत निम्न बिन्दुओं पर कार्य कर रहे है |

1. पत्राचार, RTI, DRTI और PGC में हियरिंग चल रही है | इससे अब विभाग आपस में भी फ्लोउप करने लगे है शिक्षा विभाग ने अब DUSIB से स्कूल बनाने के लिए जगह और आवंटन की बात कही है |
2. समय समय पर मध्यान भोजन को चैक करने बस्ती की महिलायें स्कूल जाती है |

3. हालाकि स्कूल बच्चों के दाखिले करने मना नहीं कर सकता इसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो गाँव से या फिर जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है उन्हें लेने में आनाकानी कर्ता है ऐसे में हमारी टीम ने 7 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया |
4. जैसाकि स्कूलों में माहौल ठीक नहीं है पढाई ठीक नहीं है आदि की सही तस्वीर निकालने के लिए सर्वे कर है जोकि अभी चल रहा है लगभग 500 छात्रों से सर्वे हो चुका है जिससे निकले आंकड़े विभागों में अधिकारीयों को भेजने और स्कूलों की स्थिति सुधारने के काम आयेंगे |

आवास और लाइसेंस

2000 में पुनर्वास के नाम पर उजाडी गई ग्यारह झोपडी बस्तियों को दिल्ली के केंद्र हटा कर भलस्वा में बसाया गया भलस्वा जैसी दिल्ली में ऐसी कई पुनर्वास कॉलोनियां है जिन्हें झोपडी बस्तियों (जेजेसी) से जबरन निकाला गया । शहर में ऐसी नीतियों का एक लम्बा इतिहास रहा है जिसमें झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को मुख्य शहर से हटाकर शहर के बाहर बसाया गया है।

इन पुनर्वास कॉलोनीयों से 7000 रूपये में 10 सालों की सिक्योरिटी और लाइसेंस शुल्क के बदले लोगों को अपनी जमीन पर 10 साल का लाइसेन्स मिला | कानूनी तौर पर यह बात भी निश्चित नहीं है कि यहाँ के निवासियों को भविष्य में एक बार फिर विस्थापित नहीं किया जाएगा |

लाइसेंस को लेकर लोगों में जागरूकता

1. सच यह भी है कि अधिकांश कॉलोनीयों में लोगों को अभी तक भी इस सच का पता नहीं है हमारे काम का अनुभव यह भी है कि यह बहुत ही संजीदा मसला है जिससे लोगों का आवास के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव भी है | लाइंसेंस से भी अधिक नाजुक मुद्दा है केंसिल प्लाट का, जब हमने लोगों के साथ केंसल प्लाट की बात की तो ही लोगो की दिल की धड़कन बढ गई और हाई ब्लडप्रेशर होने लगा था | हो भी क्यूँ नहीं लोगो ने पूरी जिंदगी की कमाई के साथ अपने गाँव की जमीन को भी बेचा है |
2. लाइसेंस के मुद्दे को भलस्वा में लोगों तक पहुचाने कोशिश की है जिसे हम हर मीटिंग में हर मुद्दे के साथ जोड़कर बताते है जिसे लेकर लोग जागरूक है लोगो का कहना है की अगर अब किसी ने भी जमीन छिनने की कोशिश की तो ये रोड पर उतरेंगें घर उनका है वह उसकी कीमत चूका चुके है |
3. पिछले साल किया गया लैंड सर्वे को लेकर हमने कई नेटवर्क कार्यक्रम में प्रस्तुती की है जिससे अन्य लोगों तक यह संदेश पहुचे की लोग आवास के लिए कितना खर्च कर चुके जिसका हिसाब सरकार से लिया जा सकता है यही नहीं कुछ बस्तियों ने इसी तर्ज पर स्वयं का सर्वे भी किया है | सर्वे के आकड़ों को भलस्वा में भी लोगों को बता कर जागरूक किया है |
4. इसी अनुभव को अन्य झोपडी बस्तियों में भी बांटा है जिससे लोगों को पुनर्वास से पहले अपनी तैयारी कर ले पुनर्वास से पहले क्या जरुरी है या जरुरी भी है की नहीं, हमें अपनी बस्ती में ही रहना है आदि |

5. विभाग के साथ चर्चा व बातचीत का नतीजा शून्य है | कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता केवल एक मौखिक वार्ता में यही कहा जाता है यह मोबाइल रिचार्ज की तरह है |
6. इसलिए भलस्वा में अभी लाइसेंस को लेकर लोगों के साथ शिकायत कैंप लगाने की तैयारी चल रही है जिससे लोग अपने मालिकाना हक़ की बात स्वयं अपने पत्र द्वारा कर सके |

स्वयं सहायता समूह (SHG)

रोजगार कि तलाश ने लोगों को शहरों में पलायन के लिए मजबूर किया किसी तरह से लोगों ने जीने लायक आवास और रोजगार कि व्यवस्था की और शहरो में झोपडी बस्ती जैसी व्यवस्था हो गई और शहरों के विकास और स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरों का विस्तार और सौन्दर्यकरण पर जोर डाला जाने लगा ऐसे में मेहनतकशों कि झोपड़ी बस्तियों को हटाने पर जोर दिया गया और इनके लिए पुनर्वास कि नीति बनी जिसके तहत लोगों को खूब सपने दिखाये लगे पुनर्वास नीति और कानूनों को ताक़ पर रख झोपडी बस्तियों को पुनर्वास के नाम उजाड़ा गया और खुले सुनसान जगहों (जंगल) में छोड़ दिया गया, सुविधाओं के नाम पर शून्य बल्कि जिससे से लोगों के रोजगार छुट गए पुनर्वास के 15 वर्षों के बाद भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है | महिलाए और घर के सभी सदस्य छोटे छोटे काम जैसे नट बोल्ड कसना और पेकिंग करना, सितारे लगाना, बिंदी चिपकाना, झाड़ू बनाना, पापड़ बनाना, लोहे पत्तियां मोड़ना, चना छिलना आदि काम करते है जिससे परिवार में दो वक्त कि रोटी का जुगाड़ होता है |

इसके अलावा कई बार महिलाओं को परिवार के कुछ खर्चों स्वास्थ्य, त्यौहार, आदि के लिए भी पैसे की जरूरत होती है जिसके लिए अधिक दर पर पैसा कर्जा लेना पड़ता है ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने स्वयं सहायता समूह से मदद ले सकती है इस बात को मध्यनजर भी SHG का गठन किया गया | यूँ तो समुदाय में अन्य संस्था व संगठनो द्वारा भी SHG चलाये जा रहे है यह बात महत्वपूर्ण है कि ऐसे में हमने फिर क्यूँ SHG बनाने का फैसला किया | हम SHG को धीरे धीरे रोजगार के साथ जोड़ेंगे जिससे समुदाय सशक्त हो और एक कदम आगे बढ सके | इस समय मंच द्वारा 5 समूहों को बनाया जा चूका है जिनके बैंक में खाते खोल दिए गए है और महिलाओं ने आपस में लोन लेना भी शुरू कर दिया है |

मकसद

1. भलस्वा के हर संघर्ष में लोगों की, विशेषकर महिलाओं कि भागीदारी रही है इन्ही महिलाओं को 5 समूहों में अलग अलग समूह के नामों से रजिस्टर्ड किया गया जिससे महिलायें अपने समुदाय का संघर्ष हो या फिर उनके घर की आर्थिक स्थिति से निपटाना | स्वयं सहायता समूहों में जुड़कर महिलाए एक दुसरे का सहयोग कर सके |

2. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हुनर विकास जैसी योजनाओं का इन समूहों को फायदा मिल सके और महिलाओं के हुनर को निखारा जा सके महिलायें रोजगार कि दिशा में कदम बाधा सके और हर तरह से सक्षम हो सके अर्थात आने वाले दिनों में इन समूहों को हुनर / कौशल कि दिशा में ले जाया जा सके जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण कि दिशा में एक और कदम बढ़ सके |

<u>समूहों के नाम</u>

- धनलक्ष्मी 20 सदस्य
- सखी 17 सदस्य
- सहेली 18 सदस्य
- चिराग 20 सदस्य
- सहयोग 18 सदस्य

<u>कर्णछपरा</u>

कर्ण छपरा में काम की शुरुवात 2013 में हमारे आउट स्टेशन विजिट से हुई जिसे मंच दिल्ली से ही संचालित कर्ता है और जरूरत पड़ने पर वहां का दौरा करना और लोगों के साथ मिलकर मुद्दे को आगे बढ़ाना रहा है | यहाँ के युवाओं को इस कार्य को लेकर काफी दिक्कतों का भी सामना करना है उनके उपर कई बार SC, ST एक्ट ,गुंडा एक्ट भी लगाया गया इसके बावजूद संघर्ष जारी है जिसमे गाँव के लोगों की सहमती भी शामिल है |

पिछले वर्ष गाँव में जांच हुई जिसमे प्रधान ने गबन किया जिस पर डीएम द्वारा रिकवरी के आदेश हुए थे और प्रधान के खाते पर रोक लगा दी गई | इस वर्ष इस पर आगे की कार्यवाही की गई |

1. गाँव के दबाव से गाँव में ग्राम सभा बुलाई गई और तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया लेकिन काफी पत्राचार और अधिकारीयों से बातचीत के बाद भी समिति को चार्ज नहीं सौपा गया |
2. प्रधान द्वारा रिकवरी पर स्टे लेलिया गया | इस स्टे का अधिकारीयों ने फायदा उठाया, लोगों से यह कह कर कि पूरे प्रकरण पर स्टे है और लोगों को बिना बताये गाँव में के और जांच की जिसमे रिकवरी पचास प्रतिशत कम हो गई जिस पर परधान ने यह रिकवरी सरकारी खजाने में जमा करा दी और प्रधान का यह कह कर खता खोल दिया गया कि अगर प्रधान द्वारा आगे से कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा |
3. गाँव इससे संतुष्ट नहीं था और गाँव बैठकें हुई और निर्णय लिया गया कि हमें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए जो की आसान नहीं था जिसके लिए पैसा भी चाहिए और इलाहाबाद के चक्कर लगाना आवश्यक होगा इसके लिए लोगों ने तय किया की कुछ भी हो वे न्याय लेकर ही रहेंगे | अब लोगो ने उसकी तयारी शुरू कर दी |
4. काफी भाग दौड़ और मेहनत के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगभग 350 पेज की याचिका को फाइल किया गया जिसमे 13 बड़े अधिकारीयों और विभाग को पार्टी बनाया गया | दुःख की बात यह की अदालत ने इसे यह कह कर ख़ारिज कर दिया कि आप शिकायतकर्ता है इसे फ़ाइल करने का आपका लोकस क्या है |

5. इस समय एक बार फिर से इसे PIL के माध्यम से फाइल करने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेजाने के लिए भी लोग तैयार है क्योकि यह मामला एक गाँव का नहीं बल्कि हजारों गाँवों का है | हैरानी की बात यह है की आज तक किसी भी गाँव का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पंहुचा है इसलिए इसे आगे लेकर जाना भी जरुरी भी है |

1.

1.<u>शिक्षा के मुद्दे पर कार्यशाला</u>

समुदाय में स्कूल जाने वाले बच्चों की समस्या और जूझते अभिवावकों की समस्या क्या क्या है और अपने स्तर पर उससे कैसे निपट सकते है इसी सम्बन्ध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे 25 महिलायें भागीदार थी जिन्होंने स्कूल के माहौल पर अपने अनुभवों को बताया और समस्याओं के निवारण के लिए चर्चा की गई साथ ही शिक्षा के अधिकार को लेकर जानकारी दी गई यह एक सफल प्रयास रहा |

2. <u>राशन के मुद्दे पर कार्यशाला</u>

नया खाद्य सुरक्षा बिल क्या है ? समुदाय में लोगों को यह समझाना अति आवश्यक था इस कार्यशाला में भलस्वा और जहांगीरपुरी की 25 महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी और राशन से जुड़े कई सवाल थे जिसका समाधान इस कार्यशाला में किया गया महिलाओं ने इस जानकारी को समझाया और लोगों तक इसे फैलाने की बात कही |

<u>कार्यक्रम / रिपोर्ट</u>

1. 8 मार्च 2014 महिला दिवस पर रचनात्मकता (रंगोली) महिलाओं की शिक्षा (साक्षरता) पर चर्चा और समुदाय का संघर्ष (RTI) पर लिखी गई पुस्तक का महिलाओं द्वारा विमोचन का कार्यक्रम था |
2. 20 अक्टूबर 2014 दिवाली सलिब्रेशन किया गया जिसमे सलिब्रेशन के साथ बस्ती की समस्याओं को भी उठाया गया | इस कार्यक्रम में 150 से 200 महिलाए एकत्र हुई |

3. 20 अक्टूबर 2014 दिवाली सलिब्रेशन किया गया जिसमे सलिब्रेशन के साथ बस्ती की समस्याओं को भी उठाया गया | इस कार्यक्रम में 150 से 200 महिलाए एकत्र हुई

4. 14 नवम्बर 2014 बाल दिवस पर बच्चो का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे 60 बच्चों ने पेंटिग के माध्यम से अपने अपने स्कूलों की समस्याओं को दर्शाया जिसकी एक प्रदर्शनी बनायी गई जिसे हमें अपने कार्यकर्म से लोगों के लिए लगाया |

5. 30 दिसम्बर 2014 बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँगीरपुरी में आयोजित किया गया 150 से 200 बच्चो ने भाग लिया जिसमे बच्चों ने कविता पाठ, गीत, नाटक और डांस द्वारा अपने हुनर का प्रदर्शन किया | इसका मकसद ही था बच्चो को अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को उभारना |

6. 17 जनवरी 2015 जन जागृति संवाद कार्यक्रम लगभग 900 से 1000 महिलाओं ने भाग लिया जिसमे संस्कृति कार्यक्रम के माध्यम से वाटर ATM जैसे मुद्दे को उठाया गया जिसमे महिलाओं ने खुल कर भागीदारी दी यही नहीं अन्य संस्थाओं और संगठनों की भी भागीदारी रही |

7. 8 मार्च 2015 महिला दिवस को जनसुनवाई के रूप में बनाया गया जिसमे लगभग 300 महिलाओं ने भाग लिया | विषय था नशा मुक्ति जिसमे कार्यक्रम को दो भागो में किया गया पहला समुदाय में फेरी के साथ लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए और दूसरा भाग जनसुनवाई के रूप में था जिसमे थाणे के SHO शामिल हुए और लोगो की शिकायतों का जबाब दिया, जिसका फोलोउप अभी चल रहा है |

<u>अन्य रिपोर्ट</u>

1. **<u>निर्माण मजदूर :-</u>**

जहांगीरपुरी समुदाय में निर्माण मजदूर के रजिस्ट्रेशन को लेकर बाहर से कई संस्थाओं ने आकर निमार्ण मजदूरों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 600 से 900 रूपये तक वसूला है लोगों ने जिसके बारे में मंच को बताया भले ही मंच सीधे मजदूरों के मुद्दों पर काम नहीं करता, समुदाय की जरूरत को देखते हुए हमने साझा मंच के घटक साथी सन्गठन (दिल्ली असंगठित निमार्ण मजदूर यूनियन) से बात की जिससे पता चला कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन मात्र 150 रूपये में होता है हांलाकि इस समय रजिस्ट्रेशन की स्कीम में कुछ बलाव हुए और खर्चा भी बढ़ गया है |

रजिस्ट्रेशन से निमार्ण से जुड़े मजदूरों को भविष्य में काफी फायदे मिलेंगे जैसे 60 वर्ष के बाद पेंशन, बच्चों की पढाई में, शादी में, स्वास्थ्य, जीवन बीमा आदि | इन्ही सब बातों को समझने के बात ही हमने लोगों की इस बात को आगे बढ़ाया |

- रजिस्ट्रेशन 58 लगों का
- 11 लोगों के रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुके है |
- मजदूरों के स्कूल जाने वाले 6 बच्चो के फंड के लिए फार्म भर चुके है |
- इक बेटी की शादी के लिए मिलने वाली राशि के लिए फार्म भरा है |

2. <u>विकलांग बच्चे का खाता</u>

एक ऐसे बच्चे की कहानी जो शारीरिक रूप से विकलांग है माँ भी मंदबुद्धि है और पिता भी एक ही आंख से रिक्शा चलाने के काम करते है ऐसे में बच्चे की विकलांग पेंशन कितनी जरुरी है यह हम समझ सकते है उसके लिए बैंक में खाता खोलना जरुरी था महीनों से धक्के खाते माँ बाप परेशान हो चुके थे जिसमे मंच के कार्यकर्ता ने भी काफी बैंकों से बात की, जिसमे काफी भाग दौड़ और मेहनत की इसके बावजूद भी बैंक खता खोलने को तैयार नहीं वजह थी बच्चे की गारंटी कौन लेगा | इस पर लोकल अखबार के रिपोर्टर का इस्तमाल किया जिसमे बैंक से बात की जिससे बैंक के अधिकारी घबरा गए और अधिकारियों ने हमारे कार्यकर्ता को फोने करके खाता खोलने के लिए बुलाया | अब बच्चे का कहता खुल गया है |